राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय
दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण गुरुवार 03 सितंबर 2026 वर्ष-9,अंक-212 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पहला कॉलम

दिल्ली हाई कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी, केवल तेज रफ्तार से चालक को लापरवाह नहीं ठहराया जा सकता

नई दिल्ली।

दिल्ली हाई कोर्ट ने सड़क हादसों से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि केवल वाहन का तेज रफ्तार से चलना यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि चालक ने लापरवाही या खतरनाक तरीके से वाहन चलाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी चालक को दोषी ठहराने के लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि उसकी ड्राइविंग वास्तव में लापरवाहीपूर्ण या असावधानीपूर्ण थी। न्यायमूर्ति चंद्रशेखरन सुधा की पीठ ने यह टिप्पणी दिल्ली सरकार की उस अपील को खारिज करते हुए की, जिसमें वर्ष 2009 के एक सड़क हादसे में महिला की मौत के मामले में टेंपो चालक को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। अदालत ने कहा, ÷वाहन तेज चलाने के लिए ही बनाए जाते हैं। केवल यह तथ्य कि वाहन तेज गति से चल रहा था, अपने आप में यह साबित नहीं करता कि चालक लापरवाह या असावधान था। हाई स्पीड और ओवर स्पीड सापेक्ष शब्द हैं।÷ मामला 12 नवंबर 2009 का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, नरेश पार्क एक्सटेंशन इलाके में एक टेंपो ने कथित तौर पर तेज और लापरवाही से चलाते हुए साइकिल को टक्कर मार दी थी। साइकिल पर एक युवक अपनी मां के साथ जा रहा था। आरोप था कि टेंपो का अगला पहिया महिला के सिर पर चढ़ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। निचली अदालत ने अगस्त 2013 में चालक को बरी कर दिया था। इसके बाद दिल्ली सरकार ने 2016 में हाई कोर्ट में अपील दायर की। हाई कोर्ट ने कहा कि मृतक महिला का बेटा इस मामले में अभियोजन पक्ष का एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी था। उसने बयान दिया कि टेंपो बहुत तेज गति से और लापरवाही से चल रहा था, लेकिन वह यह नहीं बता सका कि चालक की ड्राइविंग किस तरह लापरवाहीपूर्ण थी। वह टेंपो की अनुमानित गति भी नहीं बता पाया। अदालत ने कहा कि किसी सड़क दुर्घटना में मौत हो जाने मात्र से यह निष्कर्ष नहीं

निकाला जा सकता कि चालक लापरवाह था। हाई कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष को यह बताने के लिए ठोस सामग्री पेश करनी चाहिए थी कि मामले की परिस्थितियों में ÷तेज रफ्तार÷ का क्या अर्थ था। पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में केवल दुर्घटना के आधार पर चालक की लापरवाही नहीं मानी जा सकती।

दिल्ली में छात्रा से दरिंदगी- स्लीपर बस में मिले आरोपियों के फिंगरप्रिंट

डीएनए रिपोर्ट का इंतजार, पुलिस जल्द दाखिल करेगी चार्जशीट

नई दिल्ली ।

दिल्ली में चलती स्लीपर बस में 16 वर्षीय छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस को फोरेंसिक जांच में अहम सुराग मिले हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, जब्त की गई स्लीपर बस से पीड़िता और दोनों आरोपियों के फिंगरप्रिंट्स मैच हुए हैं। इसके अलावा बस की सीटों और स्टीयरिंग व्हील से फोरेंसिक नमूने एकत्र किए गए हैं। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर कुलदीप और कंडक्टर संदीप के कपड़े भी जब्त कर लिए हैं और अब डीएनए डीएनए रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद अदालत में जल्द चार्जशीट दाखिल की जाएगी। दोनों आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

घटना 4 अगस्त की रात की है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की रहने वाली 11वीं की छात्रा घर में कहासुनी के बाद बिना बताए नोएडा स्थित अपने रिश्तेदार के घर जाने के लिए निकली थी। मैनपुरी से आकर वह बारिश और अंधेरे के बीच ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर उतरी और वाहन का इंतजार करने लगी। इसी दौरान वहां से गुजर रही एक खाली स्लीपर बस को छात्रा ने रुकने का इशारा किया।

ड्राइवर और कंडक्टर ने उसे नोएडा सेक्टर-63 ले जाने की बात कहकर बस में बैठा लिया। बस के शीशों पर घने पर्दे लगे होने का फायदा उठाकर दोनों ने चलती बस में छात्रा के साथ दरिंदगी की और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने देर रात छात्रा को कश्मीरी गेट बस टर्मिनल के पास रिंग रोड पर छोड़ दिया और फरार हो गए। पीड़िता ने तुरंत कश्मीरी गेट पुलिस थाने पहुंचकर आपबीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बस को जब्त कर दोनों आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा।

फर्जी टोल वसूली घोटाला- ईडी ने की ताबड़तोड़ छापेमारी

- देशभर के 14 ठिकानों पर कार्रवाई

लखनऊ।

केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में एक बड़े फर्जी टोल कलेक्शन घोटाले के सिलसिले में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। एजेंसी ने आज सुबह से ही देश भर में लगभग 14 ठिकानों पर सघन सर्च ऑपरेशन चलाया। सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के सर्वर के समानांतर फर्जी/पायरेटेड सॉफ्टवेयर बनाकर की जा रही अवैध वसूली से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की जा रही है।इस घोटाले का खुलासा पहले उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने किया था, जिसमें सामने आया था कि टोल वसूली का सिर्फ 5प्रतिशत हिस्सा ही सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता था, जबकि शेष 95 प्रतिशत राशि का बड़ा गबन किया जा रहा था।

आरोपी एनएचएआई के सिस्टम को बायपास कर फर्जी फास्टैग का इस्तेमाल कर ओवरलोडेड और वाणिज्यिक वाहनों को निकालते थे, जिससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा था। प्रवर्तन निदेशालय इस पूरे नेटवर्क में धोखाधड़ी से लाभ उठाने वाले अंतिम लाभार्थियों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) की धारा 17 के तहत की जा रही इस कार्रवाई में उत्तर प्रदेश के वाराणसी समेत राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू, मध्य प्रदेश, एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) और कोलकाता स्थित परिसरों पर तलाशी ली जा रही है। छापेमारी के दौरान डिजिटल रिकॉर्ड, बैंक खातों के दस्तावेज और बेनामी संपत्तियों से जुड़े कागजात खंगाले जा रहे हैं। आरोप है कि टोल संचालकों, आईटी कर्मियों और अन्य आरोपियों के बीच अवैध रूप से जुटाई गई रकम बांटी जाती थी।

श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज अहम बैठक

सीईओ के चयन और ट्रस्ट डीड में संशोधन पर लगेगी मुहर, चंपत राय की वापसी की अटकलें तेज

अयोध्या ।

श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक बुधवार दोपहर दो बजे श्रीमणिराम जी की छावनी में आयोजित होगी। इस बैठक का मुख्य एजेंडा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के चयन की प्रक्रिया को पूरा करना है। इसके साथ ही, ट्रस्ट गठन के बाद पहली बार प्रस्तावित न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) और नियमावली में संशोधन को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। ट्रस्ट के अनुसार, अंतरिम महासचिव कृष्णमोहन के प्रस्ताव पर नियमों में बदलाव किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस संशोधन के जरिए ट्रस्टियों की नियुक्ति, त्यागपत्र के बाद पुनर्गठन और सीईओ के पद को औपचारिक रूप से स्वीकार करने जैसे नए प्रावधान जोड़े जा सकते हैं।

इस बदलाव को पूर्व महासचिव चंपत राय की वापसी के रास्ते के तौर पर भी देखा जा रहा है। रामनगरी के साधु-संतों ने खुले तौर पर चंपत राय की वापसी का समर्थन किया है।

अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजेगा इसरो,रचेगा नया इतिहास

- इस प्रक्षेपण को आम लोग भी देख सकेंगे, ऑनलाइन कराना होगा पंजीकरण

नई दिल्ली।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) 4 सितंबर 2026 को जीएसएलवी-एफ17/ईओएस-05 मिशन के तहत अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी में है। इस मिशन का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रात 2ः55 बजे तय किया गया है। इस मिशन को धरती के विस्तृत अवलोकन और उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें उपलब्ध कराने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। मीडया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक्स पर मिशन की जानकारी साझा की। ईओएस-05 से प्राप्त आंकड़ों का इस्तेमाल कृषि, आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में किया जा सकेगा। जियो-इमेजिंग उपग्रह पृथ्वी की सतह की विस्तृत तस्वीरें और जरूरी आंकड़े उपलब्ध कराते हैं। इससे फसलों की स्थिति पर नजर रखने, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों का आकलन करने और बदलती भौगोलिक परिस्थितियों को समझने में मदद मिलती है। उपग्रह से मिलने वाला डेटा सरकारी

एजेंसियों को कई अहम फैसले लेने में मदद कर सकता है। विशेष रूप से बाढ़, भूस्खलन, जंगल की आग और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों से मिलने वाली जानकारी राहत एवं बचाव अभियानों के लिए उपयोगी साबित होती है। इसके अलावा सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी और बुनियादी ढांचे की योजना बनाने में भी ऐसे उपग्रहों की भूमिका अहम होती है। इस प्रक्षेपण को आम लोग भी देख सकेंगे।

नेपाल में बाढ़ से 1100 से अधिक हुई मौतें,हजारों लापता,अब नया खतरा

काठमांडू।

नेपाल में हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, जिसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर बुधवार को 1127 हो गई। सुरक्षाबलों ने आठ जिलों से और शव बरामद किए हैं। अधिकारियों के अनुसार, यह आंकड़ा रुक-रुककर हो रही बारिश और कई जिलों में नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण बचावकर्मियों के लिए चुनौतियों के बावजूद सामने आया है। इस बीच, देश के कई हिस्सों में बाढ़ की नई चेतावनी भी जारी की गई है, जिससे चिंता और बढ़ गई है।

राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार, करीब 4,000 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें 583 विदेशी नागरिक और 83 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। वहीं, राहत और बचाव अभियानों के माध्यम से अब तक लगभग 12,000 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। यह भीषण आपदा 26 अगस्त को नेपाल-तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के खिसकने या हिमस्खलन के कारण आई अचानक बाढ़ का परिणाम है। इस प्राकृतिक आपदा ने उत्तरी और मध्य नेपाल के कस्बों तथा गांवों में भारी विनाश किया है। हिमालयी सीमा क्षेत्र से दक्षिण की ओर बहने वाली भोटेकोशी नदी अपने साथ बाढ़ का पानी निचले इलाकों में ले गई, जिससे सैकड़ों घर, वाहन, सड़कें और पुल बह गए, साथ ही कई महत्वपूर्ण जलविद्युत परियोजनाओं को भी गंभीर नुकसान पहुँचा।इस आपदा का असर सीमा पार चीन पर भी पड़ा है, जहाँ 16 लोगों की मौत हुई है और तिब्बत में करीब 550 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल के भीतर, चितवन जिले में सबसे अधिक 321 शव बरामद किए गए हैं, इसके बाद नवलपरासी ईस्ट में 216, नवलपरासी वेस्ट में 170, नुवाकोट में 142, गोरखा में 65, धाडिंग में 57, रसुवा में 41 और तनहुन में 38 शव मिले हैं। चिकित्सा केंद्रों पर अपने लापता रिश्तेदारों की तस्वीरें लिए लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है, जो दीवारों पर चिपकाई गई मृतकों की तस्वीरों को ध्यान से देख रहे हैं।

हिमालय की 9 से 12 ग्लेशियर झीलें अत्यंत खतरनाक स्थिति में-स्टडी

वैज्ञानिकों ने बढ़ते पर्यटन और प्रदूषण को बताया भविष्य का बड़ा खतरा

नई दिल्ली ।

नेपाल में ग्लेशियर झील टूटने के बाद आई विनाशकारी बाढ़ को एक सप्ताह से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन मलबे के बीच अपनों की तलाश और राहत-बचाव कार्य अब भी जारी है। हजार से ज्यादा लोगों की मौत और 4 हजार से अधिक लोगों के लापता होने की इस त्रासदी के बीच आईआईटी मंडी की स्टडी ने भविष्य के लिए गंभीर चेतावनी जारी की है। संस्थान की शोध रिपोर्ट के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश और आसपास के हिमालयी क्षेत्रों की करीब 200 झीलों में से 9 से 12 ग्लेशियर झीलें क्रिटिकल यानी बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच चुकी हैं, जो कभी भी नेपाल जैसे भीषण हादसे को अंजाम दे सकती हैं।

आईआईटी मंडी के स्कूल ऑफ सिविल एंड एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. डेरिक्स पी. शुक्ला के अनुसार, पिछले एक दशक में हिमाचल की कई ग्लेशियर झीलों का आकार 30 से 60 प्रतिशत तक बढ़ा है। एनडीएमए ने जहां घेपन, वासुकी, काशांग और बास्पा के पास स्थित 4 झीलों को संवेदनशील माना है, वहीं आईआईटी मंडी के सर्वे में 9 से

12 झीलों को बेहद खतरनाक श्रेणी में रखा गया है। इनमें घेपन, योचे और काली कुंड से सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि इनके निचले इलाकों में घनी आबादी बसती है। पर्यटन और पर्माफ्रॉस्ट पिघलना बना मुख्य कारण शोधकर्ताओं का कहना है कि पहाड़ी इलाकों में बेकाबू पर्यटन, टनल निर्माण और वाहनों की आवाजाही से उत्सर्जित कार्बन और धूल बर्फ पर जमा हो रही है। यह काली परत सूर्य की किरणों को अधिक अवशोषित कर ग्लेशियरों को तेजी से पिघला रही है। इसके अलावा, जमीन के नीचे जमी रहने वाली परत (पर्माफ्रॉस्ट) के पिघलने से पहाड़ों की ऊपरी चट्टानें और मिट्टी बेहद कमजोर हो रही हैं।

देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के आसार,दिल्ली में येलो अलर्ट जारी

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में बारिश के साथ आंधी-तूफान की संभावना

नई दिल्ली।

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई हिस्सों में, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी भी शामिल है, आंधी-तूफान, बिजली गिरने और भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बुधवार को दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने और कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। सुबह से दोपहर के बीच कुछ जगहों पर आंधी-तूफान और बिजली गिरने के साथ भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

इस सप्ताह पश्चिमी हिमालय और उत्तरी मैदानी इलाकों के कुछ हिस्सों में व्यापक बारिश होने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में रुक-रुक कर बारिश होने हो सकती है, जबकि हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में व्यापक बारिश होने की संभावना है।

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में बारिश के साथ आंधी-तूफान और बिजली गिर सकती है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी व्यापक बारिश होने की संभावना है, जबकि बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी बारिश हो सकती है। इस क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में बड़े पैमाने पर बारिश हो सकती है, साथ ही पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी रुक-रुक कर बारिश हो सकती है। इस इलाके के कुछ हिस्सों में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा में भी बारिश हो सकती है, जबकि गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और सौराष्ट्र-कच्छ में छिटपुट बारिश हो सकती है। तटीय कर्नाटक में भी बड़े बारिश के आसार है, जबकि केरल और लक्षद्वीप में भी बारिश का दौर चल सकता है। दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों, जिनमें रायलसीमा, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश शामिल हैं।

पीयूष गोयल जी20 व्यापार मंत्रियों की बैठक और भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता के लिए अमेरिका जाएंग-सर्जियो गोर

नई दिल्ली।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस महीने के अंत में अमेरिका की यात्रा करेंगे, जहां वह जी20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के साथ-साथ दोनों देशों के बीच जारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते की वार्ता पर चर्चा करेंगे। यह जानकारी भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने बुधवार को दी।

ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसीएमए) के 66वें वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं और वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

अमेरिकी राजदूत ने कहा कि आने वाले हफ्तों में वॉशिंगटन में जी20 वार्ता की मेजबानी के दौरान गोयल अमेरिका का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों सरकारें ऐसे व्यापारिक संबंध बनाने की दिशा में काम कर रही हैं, जो निष्पक्ष, पारस्परिक और दोनों देशों के लिए लाभकारी हों।

यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

गोर ने कहा, ÷अपने अच्छे मित्र और वाणिज्य मंत्री के साथ होना बहुत अच्छा है। अमेरिका और भारत बहुत करीबी से मिलकर काम कर रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है।÷ उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन जी20 बैठकों के लिए गोयल की मेजबानी करने को लेकर उत्सुक है।

गोर ने दोनों देशों के बीच हुई

प्रगति का भी जिक्र किया, जिसमें दोनों सरकारों के बीच बनी व्यापार संबंधी समझ भी शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच सहयोग केवल वस्तुओं के व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं। व्यापक सहयोग पर प्रकाश डालते हुए अमेरिकी राजदूत ने कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में साझेदारी कर रहे हैं। उन्होंने इस साल की शुरुआत में हस्ताक्षरित पैक्ट सिलिका घोषणा का भी जिक्र किया। गोर के अनुसार, इस घोषणा का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देने वाला नियामकीय ढांचा तैयार करना और अमेरिकी एवं भारतीय कंपनियों द्वारा सीमा-पार निवेश को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि यह पहल दोनों देशों में उद्यमियों और नए कारोबार खड़े करने वाली अगली पीढ़ी को सशक्त बनाने में भी मदद करेगी।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

युद्ध और टैरिफ के तूफान में भी भारत की अर्थव्यवस्था का बजा डंका

(लेखक - कांतिलाल मांडोत)

7.8 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि ने दुनिया को दिया भारत की आर्थिक ताकत का संदेश, सरकार की नीतियों और मजबूत कार्यप्रणाली का दिखा असर

दुनिया इस समय आर्थिक और सामरिक अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद पैदा हुई वैश्विक परिस्थितियों ने पहले ही ऊर्जा और आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित कर रखा था। इसके बाद अमेरिका-ईरान तनाव और युद्ध ने वैश्विक बाजारों की चिंता बढ़ा दी। होर्मुज क्षेत्र में पैदा हुए संकट का असर तेल और समुद्री व्यापार पर पड़ा। भारत के आयात-निर्यात पर भी इसका दबाव महसूस किया गया। दूसरी ओर अमेरिका की ओर से भारत पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी और व्यापारिक दबाव ने परिस्थितियों को और चुनौतीपूर्ण बना दिया। इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने जिस मजबूती का प्रदर्शन किया है, वह केवल एक आर्थिक आंकड़ा नहीं बल्कि देश की आर्थिक क्षमता और नीतिगत स्थिरता का बड़ा संकेत है।

वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत दर्ज की गई है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9 प्रतिशत थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आंकड़ा भारतीय रिजर्व बैंक के लगभग 7 प्रतिशत के अनुमान से भी बेहतर रहा। वैश्विक स्तर पर जब अनेक अर्थव्यवस्थाएं युद्ध, महंगाई, ऊर्जा संकट और व्यापारिक तनाव से जूझ रही हैं, तब भारत की अर्थव्यवस्था का इस गति से आगे बढ़ना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है।

भारत की इस आर्थिक तस्वीर को केवल बाजार की स्वाभाविक ताकत के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसके पीछे सरकार की लगातार बनाई गई आर्थिक रणनीति और उस रणनीति को जमीन पर लागू करने की कार्यप्रणाली भी महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने विकास का आधार केवल तत्काल राहत या उपभोग को नहीं बनाया, बल्कि बुनियादी ढांचे, सड़क, रेल, बंदरगाह, ऊर्जा, रक्षा, विनिर्माण और डिजिटल अर्थव्यवस्था में लगातार निवेश बढ़ाने पर जोर दिया है। यही पूंजीगत खर्च आज आर्थिक गतिविधियों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

पहली तिमाही में सरकार के पूंजीगत खर्च में 18.6 प्रतिशत की वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि सरकार आर्थिक दबाव के समय भी विकास खर्च को रोकने के बजाय उसे आगे बढ़ाने की नीति पर कायम है। सरकार का यह दृष्टिकोण अर्थव्यवस्था के लिए दोहरा लाभ पैदा करता है। एक ओर बड़े स्तर पर निर्माण और आधारभूत ढांचे की परियोजनाओं से रोजगार और कारोबार को बढ़ावा मिलता है, वहीं दूसरी ओर सड़क, रेलवे, बिजली, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक ढांचे में सुधार से आने वाले वर्षों की आर्थिक क्षमता मजबूत होती है।

भारत की अर्थव्यवस्था में सरकारी निवेश का असर निजी क्षेत्र की गतिविधियों पर भी दिखाई देता है। जब सरकार बुनियादी ढांचे में निवेश करती है तो उससे सीमेंट, स्टील, मशीनरी, परिवहन, निर्माण और अनेक दूसरे क्षेत्रों में मांग पैदा होती है। इससे अर्थव्यवस्था में पैसा घूमता है और निजी क्षेत्र को भी विस्तार का अवसर मिलता है। यही कारण है कि वर्तमान आर्थिक वृद्धि को केवल सरकारी खर्च से जोड़ना उचित नहीं होगा। सरकार द्वारा तैयार किया गया वातावरण निजी निवेश और उपभोग दोनों के लिए आधार तैयार कर रहा है।

आम लोगों की खपत भी आर्थिक वृद्धि का एक महत्वपूर्ण आधार बनी हुई है। पिछले वर्ष जीएसटी और आयकर से संबंधित राहतों के कारण लोगों के हाथ में खर्च करने योग्य आय बढ़ी। महंगाई की चुनौतियों के बावजूद उपभोक्ता मांग में अपेक्षित कमजोरी नहीं आई। इसका असर यात्री वाहनों की बिक्री में दिखाई दिया, जहां पहली तिमाही में 25.6 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर्ज की गई। यह आंकड़ा बताता है कि घरेलू बाजार में उपभोक्ता विश्वास अभी भी मजबूत है।

बिजली की मांग में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बिजली की मांग की वृद्धि दर 1.9 प्रतिशत से बढ़कर 8.4 प्रतिशत तक पहुंचना औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने का संकेत माना जा सकता है। जब उद्योग, सेवा क्षेत्र, निर्माण और घरेलू खपत में गतिविधियां बढ़ती हैं तो ऊर्जा की मांग भी बढ़ती है। इसलिए बिजली की मांग का यह आंकड़ा अर्थव्यवस्था की व्यापक गतिविधियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।

सकल मूल्य वर्धित यानी जीवीए के आंकड़े भी भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती को रेखांकित करते हैं। पहली तिमाही में वास्तविक जीवीए वृद्धि 8.2 प्रतिशत रही, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 7.1 प्रतिशत थी। वहीं नॉमिनल जीवीए वृद्धि 11.5 प्रतिशत दर्ज की गई। नॉमिनल जीडीपी वृद्धि भी 8.1 प्रतिशत से बढ़कर 10.3 प्रतिशत हुई। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि आर्थिक गतिविधियों का विस्तार केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है।

सेवा क्षेत्र की मजबूती भी भारत की आर्थिक कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी पीएमआई 58.6 तक पहुंचना बताता है कि सेवा क्षेत्र में कारोबारी गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं। भारत लंबे समय से सेवा क्षेत्र की अपनी क्षमता के लिए दुनिया में पहचान रखता है। सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, डिजिटल सेवाओं, संचार, व्यापार और अन्य सेवा क्षेत्रों का विस्तार भारतीय अर्थव्यवस्था को लगातार नया आधार दे रहा है।

सरकार की कार्यप्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उसने वैश्विक संकटों के बीच आर्थिक गतिविधियों को सामान्य बनाए रखने पर लगातार जोर दिया। रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान ऊर्जा और खाद्य बाजार में भारी उतार-चढ़ाव आया। बाद में पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा और समुद्री व्यापार तथा तेल आपूर्ति को लेकर चिंताएं पैदा हुईं। ऐसे समय में किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए आयात लागत और महंगाई को नियंत्रित रखना बड़ी चुनौती होती है। भारत ने ऐसी परिस्थितियों में आर्थिक गतिविधियों को बनाए रखने के लिए नीतिगत स्तर पर संतुलन साधने की कोशिश की।

अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव भी भारत के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में आया। भारत पर भारी टैरिफ लगाने की धमकियों ने यह आशंका पैदा की कि इसका भारतीय निर्यात और औद्योगिक उत्पादन पर गंभीर असर पड़ सकता है। लेकिन भारत ने अपनी आर्थिक रणनीति को केवल किसी एक बाजार पर निर्भर नहीं रखा। निर्यात बाजारों के विविधीकरण, घरेलू मांग को मजबूत करने, उत्पादन क्षमता बढ़ाने और विनिर्माण को प्रोत्साहन देने की दिशा में सरकार की नीतियां इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं।

भारत की आर्थिक नीति में आत्मनिर्भरता का अर्थ दुनिया से अलग होना नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति मजबूत करना है। सरकार ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ विदेशी निवेश आकर्षित करने, विनिर्माण क्षमता बढ़ाने और रणनीतिक क्षेत्रों में देश की निर्भरता कम करने की दिशा में कदम उठाए हैं। रक्षा उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, मोबाइल निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में लगातार क्षमता निर्माण इसी सोच का हिस्सा है।

आज भारत के सामने सबसे बड़ा अवसर यह है कि वैश्विक कंपनियां अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता चाहती हैं। यदि भारत इस अवसर को पूरी तरह भुना पाता है तो आने वाले वर्षों में विनिर्माण और निर्यात के क्षेत्र में उसकी भूमिका और मजबूत हो सकती है। इसके लिए सरकार की नीतिगत स्थिरता, तेज निर्णय लेने की क्षमता और परियोजनाओं को समय पर पूरा कराने की कार्यप्रणाली महत्वपूर्ण होगी।

यह भी समझना जरूरी है कि 7.8 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि उत्सव का विषय जरूर है, लेकिन इसे अंतिम उपलब्धि नहीं माना जा सकता। भारत के सामने रोजगार सृजन, ग्रामीण मांग, महंगाई, निर्यात प्रतिस्पर्धा, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक व्यापार में बढ़ते संरक्षणवाद जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। इसलिए सरकार के सामने आगे भी यही चुनौती रहेगी कि आर्थिक वृद्धि को अधिक व्यापक बनाया जाए और उसका लाभ समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचे।

फिर भी वर्तमान आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था ने बाहरी दबावों के सामने उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है। युद्ध हो, तेल संकट हो, वैश्विक व्यापार में तनाव हो या टैरिफ का दबाव—भारत की आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह पटरी से नहीं उतरीं। इसके पीछे मजबूत घरेलू बाजार, बढ़ता सरकारी पूंजीगत खर्च, सेवा क्षेत्र की क्षमता, सुधारों की निरंतरता और आर्थिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण योगदान है।

भारत आज विश्व शक्ति बनने की दिशा में केवल सामरिक या राजनीतिक आधार पर नहीं बढ़ रहा है। आर्थिक शक्ति किसी भी राष्ट्र की वैश्विक स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण आधार होती है। 7.8 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि इसी आर्थिक क्षमता का संकेत देती है। सरकार ने जिस तरह बुनियादी ढांचे, सउत्पादन, डिजिटल अर्थव्यवस्था, निवेश और घरेलू मांग को एक साथ आगे बढ़ाने की कोशिश की है, उसका परिणाम आर्थिक आंकड़ों में दिखाई देने लगा है।

सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने संकटों के बीच अपनी गति बनाए रखने की क्षमता दिखाई है। दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता बनी हुई है और आगे भी अनेक चुनौतियां सामने आ सकती हैं। लेकिन यदि सरकार इसी तरह वित्तीय अनुशासन, पूंजीगत निवेश, नीतिगत स्थिरता और आर्थिक सुधारों के बीच संतुलन बनाए रखती है तो भारत की विकास यात्रा और तेज हो सकती है।

आज 7.8 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि भारत के लिए केवल एक आंकड़ा नहीं है। यह उस आर्थिक आत्मविश्वास का संकेत है जिसके आधार पर भारत वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका और मजबूत कर रहा है। युद्ध और टैरिफ के दबाव के बावजूद अर्थव्यवस्था की यह रफ्तार बताती है कि भारत ने कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का संकल्प नहीं छोड़ा है। सरकार की कार्यप्रणाली और आर्थिक नीतियों की असली परीक्षा भी यही है कि संकट चाहे कितना बड़ा हो, विकास की गति को थमने न दिया जाए। फिलहाल जीडीपी के आंकड़े यही संदेश दे रहे हैं कि भारत की आर्थिक गाड़ी न केवल चल रही है, बल्कि वैश्विक उथल-पुथल के बीच भी अपनी रफ्तार बनाए हुए है।

(वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार स्तम्भकार)

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

संपादकीय

उम्मीद से ज्यादा तेज़ी

ऐसे वक्त में जब अमेरिका-ईरान युद्ध से कच्चे तेल के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई और आपूर्ति श्रृंखला बाधित रही, देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती का संकेत सुखद ही कहा जायेगा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद दर 7.8 रही है। यह प्रदर्शन केंद्रीय बैंक आरबीआई के सात फीसदी की विकास दर के अनुमान से भी अधिक है। यह दर बाजार की उम्मीदों से भी अधिक है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष, ऊर्जा बाजार में उतार-चढ़ाव और ग्लोबल अनिश्चितता के बावजूद देश सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है। दरअसल, इस तेज विकास दर को पाने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन से मदद मिली है। वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में सेवा क्षेत्र में दस फीसदी की विकास दर उत्साहजनक रही है। विनिर्माण क्षेत्र में 9.2 तथा निर्माण क्षेत्र में विकास दर 7.7 फीसदी की वृद्धि ने देश की आर्थिकी को गति दी है। दरअसल,औद्योगिक विकास ने भी सकल विकास दर को संबल दिया । इससे भारतीय घरेलू अर्थव्यवस्था के महत्व का पता चलता है। उल्लेखनीय है इस दौरान देश में उपभोक्ता मांग अच्छी बनी रही। वास्तव में देश के बड़े उपभोक्ता बाजार ने वैश्विक मांग और व्यापार में आई शिथिलता के बावजूद स्वदेशी आर्थिकी को मजबूती दी है। भले ही देश का विपक्ष इस कामयाबी को आंकड़ों की बाजीगरी बता रहा है लेकिन सरकार इस उपलब्धि पर अपनी पीठ थपथपा सकती है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि वैश्विक स्तर पर जारी अस्थिरता के चलते भविष्य में पैदा होने वाले जोखिम कम नहीं हो जाते हैं। विकास दर के इन आंकड़ों के चलते हमें लापरवाह होने से बचना चाहिए। पूंजीगत सामान के ज्यादा उत्पादन व सरकारी पूंजीगत व्यय में वृद्धि से पता चलता है कि देश में संरचनात्मक विकास व निवेश की मांग बनी हुई है। वास्तव में देश के नीति-नियंताओं को हमारी खाद्य श्रृंखला को मजबूती देने वाले और महंगाई को प्रभावित करने वाले कृषि उत्पादन में तेजी लाने की जरूरत है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों के बीच इस बार देश के विभिन्न क्षेत्रों में हुई असमान बारिश का असर भी कृषि उत्पादन पर पड़ सकता है। देश का कृषि क्षेत्र अभी भी मौसम की मार के प्रति संवेदनशील बना हुआ है। बहरहाल, पहली तिमाही के उत्साहवर्धक आंकड़े देश की वार्षिक विकास की अनुमानित दर में संशोधन करने की जरूरत को बताते हैं। यदि देश में घरेलू मांग और निवेश मजबूत बने रहते हैं तो हमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वार्षिक विकास दर का 6.7 फीसदी का अनुमान कम लग सकता है। इसके बावजूद, एक अच्छे तिमाही नतीजों का मतलब यह नहीं है कि आसन्न जोखिम से पूरी तरह बचा जा सकता है। ध्यान रहे कि 7.8 फीसदी की विकास दर पिछली तिमाही की 8.6 फीसदी की वृद्धि दर के मुकाबले थोड़ा कम है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में जारी अनिश्चितताएं अभी बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। वैश्विक कारोबारी तनाव, भू-राजनीतिक टकराव और ऊर्जा आपूर्ति में लगातार जारी संभावित बाधाओं से हमारा लागत मूल्य बढ़ सकता है। जिससे देश के निर्यातों में वृद्धि की संभावनाएं कमजोर हो सकती हैं। भारत जैसे देश के लिये कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, जो अपने अधिकांश ऊर्जा संसाधनों का आयात करता है। जरूरी यह भी है कि देश की विकास दर में दर्शाई जा रही तेजी का अहसास आम आदमी की जिंदगी में भी दिखायी दे। देश की आंतरिक स्थितियों पर भी ध्यान देना जरूरी है। विकास दर वृद्धि के सम्मोहन में देश में महंगाई और बेरोजगारी की समस्या की अनदेखी नहीं की जा सकती। बहरहाल, जहां सरकार विकास दर को सुधारों का प्रतिफल बता रही है, वहीं विपक्ष जीडीपी के अनुमानों के तरीकों पर सवाल उठा रहा है। ऐसी जांच-पड़ताल व बहस ठोस सबूतों पर आधारित होनी चाहिए। बहरहाल, सरकार को विकास दर के आंकड़ों से आत्ममुग्ध नहीं होना चाहिए।

आईआईएस अधिकारी केवल संचारक नहीं,शासन और जनता के बीच मजबूत कड़ी

(लेखक-विनोद सिंह 'तकियावाला')

*सटीकता,विश्वसनीयता और संवेदनशीलता के साथ नागरिकों की आकांक्षाओं को शासन तक पहुँचाने की अंहम जिम्मेदारी

नई दिल्ली।लोकतंत्र में सरकार और जनता के बीच संबंध केवल नीतियों, योजनाओं और निर्णयों से निर्धारित नहीं होते, बल्कि इन दोनों के बीच होने वाला संवाद इस रिश्ते की वास्तविक मजबूती तय करता है।सरकार की नीतियां कितनी भी जनकल्याणकारी क्यों न हों, यदि उनकी सही जानकारी नागरिकों तक नहीं पहुँचती अथवा जनता उन नीतियों के उद्देश्य और लाभ को समझ नहीं पाती, तो शासन और नागरिकों के बीच विश्वास की वह कड़ी मजबूत नहीं हो सकती, जिसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे अधिक आवश्यकता होती है।

इसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के केंद्र में भारतीय सूचना सेवा यानी आईआईएस के अधिकारी आते हैं। इन अधिकारियों की भूमिका केवल सरकार की सूचनाओं, योजनाओं और उपलब्धियों को मीडिया अथवा जनता तक पहुँचाने तक सीमित नहीं है।वे शासन और नागरिकों की आकांक्षाओं के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु हैं।उनकी जिम्मेदारी सरकार की बात जनता तक पहुँचाने के साथ-साथ जनता की आवाज,अपेक्षाओं और प्रतिक्रियाओं को शासन तक पहुँचाने की भी है।सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने आईआईएस अधिकारियों की इसी व्यापक भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा है कि उनकी जिम्मेदारी संचार से आगे बढ़कर शासन और नागरिकों के बीच विश्वास निर्माण की है। यह विश्वास सटीकता,विश्वसनीयता और संवेदनशीलता के आधार पर ही कायम किया जा सकता है।आज के दौर में इस भूमिका का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल माध्यमों ने संचार की गति को अभूतपूर्व बना दिया है। किसी घटना,सरकारी निर्णय अथवा योजना से संबंधित सूचना कुछ ही क्षणों में देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँच सकती है।सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना का प्रसार तेज हुआ है, मगर इसी के साथ गलत सूचना, अधूरी जानकारी और भ्रामक दावों की चुनौती भी गंभीर हुई है।ऐसे वातावरण में आईआईएस अधिकारियों की जिम्मेदारी केवल सूचना को तेजी से प्रसारित करने की नहीं,बल्कि सही और प्रमाणिक सूचना को सही संदर्भ में जनता तक पहुँचाने की है। सरकारी संचार में एक छोटी-सी तथ्यात्मक गलती भी नागरिकों के विश्वास को प्रभावित कर सकती है।इसके विपरीत स्पष्ट,तथ्यपरक और पारदर्शी संवाद सरकार और जनता के बीच भरोसे को मजबूत करता है।सरकारी योजनाओं और नीतियों के प्रचार-प्रसार को भी इसी दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है।किसी योजना की घोषणा कर देना और उसके आंकड़े जारी कर देना संचार की पूर्ण प्रक्रिया नहीं है।वास्तविक चुनौती यह है कि आम नागरिक उस योजना का उद्देश्य समझ सके, यह जान सके कि उसका लाभ किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है और उसके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा।यहीं आईआईएस अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।उन्हें जटिल सरकारी नीतियों और प्रशासनिक भाषा को सरल,स्पष्ट और जनसुलभ भाषा में प्रस्तुत करना होता है। जनता को केवल यह बताना पर्याप्त नहीं कि सरकार ने क्या निर्णय लिया है, बल्कि यह भी समझाना आवश्यक है कि निर्णय क्यों लिया गया और उससे नागरिकों को क्या लाभ होगा।भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में यह जिम्मेदारी और चुनौतीपूर्ण है। देश के अलग-अलग हिस्सों में भाषा,संस्कृति,सामाजिक परिस्थितियों और नागरिकों की प्राथमिकताएं अलग-अलग हैं। इसलिए सरकारी संचार को केवल एक औपचारिक संदेश तक सीमित नहीं रखा जा सकता।उसे स्थानीय परिस्थितियों और समाज की संवेदनशीलताओं के अनुरूप भी बनाया जाना आवश्यक है।आईआईएस अधिकारी इसी विविधता को ध्यान में रखते हुए सरकार और समाज के बीच संवाद को अधिक प्रभावी बना सकते हैं।उन्हें शासन की भाषा को जनता की भाषा में बदलने के साथ-साथ जनता की आकांक्षाओं को शासन तक पहुँचाने वाला माध्यम भी बनना होगा।लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवाद एकतरफा नहीं हो सकता।यदि सरकार केवल अपनी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी जनता तक पहुँचाती रहे और नागरिकों के सवालों, समस्याओं तथा प्रतिक्रियाओं को सुनने की व्यवस्था कमजोर हो,तो संवाद अधूरा रह जाता है। वास्तविक लोकतांत्रिक संचार वही है जिसमें सरकार बोलती भी है और जनता को सुनती भी है।आईआईएस अधिकारी इस दोतरफा संवाद की महत्वपूर्ण कड़ी हैं।मीडिया और जनता के साथ उनका संपर्क उन्हें समाज की बदलती सोच और अपेक्षाओं को समझने का अवसर देता है। यह जानकारी शासन के लिए भी उपयोगी हो सकती है। जनता किन मुद्दों को लेकर चिंतित है, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में कहां कठिनाइयां हैं और किन क्षेत्रों में अधिक जानकारी की आवश्यकता है,इन सबका संज्ञान लेकर संचार व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।संचार में संवेदनशीलता का महत्व भी कम नहीं है।आंकड़ों और सरकारी उपलब्धियों के पीछे आम नागरिक का जीवन जुड़ा होता है।किसी किसान,श्रमिक,महिला, युवा,वरिष्ठ नागरिक अथवा छोटे उद्यमी के लिए सरकारी योजना का अर्थ केवल एक आंकड़ा नहीं,बल्कि उसके जीवन में संभावित बदलाव है।इसलिए सरकारी संचार में मानवीय दृष्टिकोण आवश्यक है।

आईआईएस अधिकारियों को तकनीकी दक्षता के साथ इस मानवीय पक्ष को भी समझना होगा। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकारी संदेश केवल बड़े शहरों और डिजिटल माध्यमों तक सीमित न रहे, बल्कि समाज के उन वर्गों तक भी पहुँचे जो सूचना के आधुनिक साधनों तक समान रूप से पहुंच नहीं रखते। आज सरकारी संचार के सामने एक और बड़ी चुनौती विश्वसनीयता की है।जब नागरिकों के सामने सूचनाओं के अनेक स्रोत मौजूद हों,तब आधिकारिक सूचना की विश्वसनीयता तभी कायम रह सकती है जब उसमें तथ्य, पारदर्शिता और जिम्मेदारी दिखाई दे।आईआईएस अधिकारियों को इस विश्वास की रक्षा करनी होगी।उनकी भूमिका इसलिए केवल 'सरकारी सूचना पहुँचाने वाले अधिकारी' की नहीं है।वे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संवाद के प्रतिनिधि हैं।उनके माध्यम से सरकार की नीतियां जनता तक पहुँचती हैं और जनता की आवाज शासन तक जाती है। इसीलिए उनके काम में प्रशासनिक दक्षता के साथ पत्रकारिता की समझ,सामाजिक संवेदनशीलता और लोकतांत्रिक मूल्यों की गहरी समझ भी आवश्यक है।वर्तमान समय में सरकार और नागरिकों के बीच विश्वास की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है।यह विश्वास केवल घोषणाओं से नहीं बनता।इसके लिए निरंतर संवाद,सही जानकारी,स्पष्ट भाषा, पारदर्शिता और जनता की भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता जरूरी है । आईआईएस अधिकारी इस पूरी प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभा सकते हैं।

राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व

आर्थिक और सामाजिक असमानता राष्ट्रीय एकता में बहुत बड़ी बाधा है। उस असमानता का मूल है अहं और स्वार्थ। इसलिए राष्ट्र की भावात्मक एकता के लिए अहं-विसर्जन और स्वार्थ-विसर्जन को मैं बहुत महत्व देता हूं। जातीय असमानता भी राष्ट्रीय एकता का बहुत बड़ा विघ्न है। उसका भी मूल कारण अहं ही है। दूसरों से अपने को बड़ा मानने में अहं पुष्ट होता है और आदमी अपने-आप में संतोष का अनुभव करता है। अहं का विसर्जन किए बिना जातीय भेद का अंत नहीं हो सकता।

मनुष्य जन्मना मनुष्य का शत्रु नहीं है। एक पेड़ की दो शाखाएं परस्पर विरोधी कैसे हो सकती हैं? फिर भी यह कहा जाता है कि धर्म-संप्रदाय मनुष्यों में मैत्री स्थापित करने के लिए प्रचलित हुए हैं। उनमें जन्मना शत्रुता नहीं है, फिर मैत्री स्थापित करने की क्या आवश्यकता हुई? मैं फिर इस विश्वास को दोहराना चाहता हूं कि मनुष्य-मनुष्य में स्वभावतः शत्रुता नहीं है। वह निहित स्वार्थ वाले लोगों द्वारा उत्पन्न की जाती है। उसे मिटाने का काम धर्म-संप्रदाय ने प्रारंभ किया, किंतु आगे चलकर वे स्वयं निहित स्वार्थ वाले लोगों से घिर गए और मनुष्य को मनुष्य का शत्रु मानने के सिद्धांत की पुष्टि में लग गए। इस चिंतन के आधार पर मुझे लगता है कि सांप्रदायिक समस्या का मूल भी अहं और स्वार्थ को छोड़कर अन्यत्र नहीं खोजा जा सकता। इसलिए सांप्रदायिक वैमनस्य की समस्या को सुलझाने के लिए भी अहं और स्वार्थ का विसर्जन बहुत आवश्यक है।

भाषा, जो दूसरों तक अपने विचारों को पहुंचाने का माध्यम है, को भी राष्ट्रीय एकता के सामने समस्या बनाकर खड़ा कर दिया जाता है। अपनी भाषा के प्रति आकर्षण होना अस्वाभाविक नहीं है। पर हमें इस तथ्य को नहीं भुला देना चाहिए कि मातृभाषा के प्रति जितना हमारा आकर्षण होता है, उतना ही दूसरों को अपनी मातृभाषा के प्रति होता है। इसलिए भाषाई अभिनिवेश में फंसना कैसे तर्कसंगत हो सकता है। राष्ट्रीय एकता के लिए इन विषयों पर गंभीर चिंतन करना आवश्यक है।

विचार मंथन

रूस अमेरिका सहित दुनिया के अधिकांश देशों में आर्थिक संकट की आहट

(लेखक - सनत जैन/ईएमएस)

अमेरिका की अर्थव्यवस्था संकट में पड़ गई है। ईरान के साथ युद्ध के बाद अमेरिका आर्थिक एवं सामरिक दृष्टि से बहुत कमजोर हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद जिस तरह से टैरिफ नीतियों को लेकर यूरोप, नाटो सहित दुनिया के अधिकांश देशों के साथ जिस तरह की दादागिरी की। जिस तरह से ट्रम्प ने टैरिफ लगाया, उससे अमेरिका की आर्थिक स्थिति लगातार गड़बड़ाती चली गई। अमेरिका में महंगाई बढ़ी तेजी के साथ बड़ी इसी बीच ईरान के साथ युद्ध शुरू हुआ। अमेरिका को अहंकार था, वह 15 20 दिन में ईरान को ठिकाने लगा देंगे। ईरान को तो वह ठिकाने लगा नहीं पाए, उल्टे अरब देशों से अमेरिका के पैर उखड़ गए। सारे अमेरिकी सैन्य अड्डे बर्बाद हो गए। 70 फ़ीसदी हथियार खत्म हो गए, जो डर और भय अमेरिका को लेकर सारी दुनिया में बना हुआ था, वह डर और भय भी खत्म हो गया। ट्रंप की नीतियों के कारण डॉलर का दबदबा भी सारी दु निया से खत्म होता जा रहा है। डॉलर के मुकाबले अन्य मुद्राओं से वै श्विक कारोबार शुरू हो चुका है। जिसके कारण अमेरिका आर्थिक रूप से विभिन्न कारणों से कमजोर होता चला जा रहा है। अमेरिका में महंगाई के कारण त्राहिमाम मचा हुआ है। कुछ इसी तरह की स्थिति रूस की भी है। पिछले कई वर्षों से यूक्रेन के साथ वह युद्ध लड़ रहा है। भारी आर्थिक एवं साम रित नुकसान रुस को उठाना पड़ा है। रूस की आर्थिक स्थिति भी तेजी से खराब हो रही है। उसे अपना सोना बेचना पड़ रहा है। इसके बाद भी युद्ध कब खत्म होगा इसका कोई अता पता नहीं है। रूस और अमेरिका का जो अहंकार था, वह यूक्रेन और ईरान ने एक तरह से तोड़ दिया है। रूस और अमेरिका को युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। यही हाल इजराइल का हुआ है। उनका अहंकार उनके आड़े आ रहा है। इसी बीच चीन ने बड़ी शांति के साथ जब दो महाशक्तियां और दुनिया के अधिकांश देश आपस में लड़ रहे थे। इसका फायदा उठाते हुए व्यापार के जरिए अपनी आर्थिक और सामरिक स्थिति को मजबूत कर लिया। चीन एक नई महाशक्ति के रूप में सारी दुनिया के सामने है। चीन के बिना किसी का काम नहीं चल रहा है। इसमें सबसे ज्यादा खराब स्थिति भारत की है। भारत दो पाटों के बीच में फंसकर बुरी तरह से पिस रहा है। भारत अपने आप को विश्व गुरु के रूप में प्रचारित करके तथा सबसे बड़ा बाजार होने का अहंकार पालकर जिस तरह की गलतियां पिछले एक दशक से कर रहा है। उसके कारण भारत की आर्थिक स्थिति भी दिनों दिन खराब होती जा रही है। सरकार कोई भी दावा करे, उन दावों के विपरीत भारत की आर्थिक स्थिति है। भारत के ऊपर कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। भारत का सामरिक खर्च बढ़ता चला जा रहा है। 20 से 25 करोड युवा बेरोजगारी के शिकार हैं। गरीब आदमी गरीब होता चला जा रहा है। महंगाई बढ़ती चली जा रही है। 80 करोड लोगों को मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है। इसके बाद भी भारत सरकार भी जिस तरह से रूस और अमेरिका अपने अहंकार से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कुछ वही स्थिति भारत की देखने को मिल रही है। भारत चीन के ऊपर निर्भर होता चला जा रहा है। चीन का आयात भारत में साल दर साल बढ़ता चला जा रहा है। उसके मुकाबले निर्यात घटता जा रहा है।

भारत का व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। भारत और चीन के बीच में प्रतिस्पर्धा है। सीमा विवाद है, भारतीय सीमाओं पर चीन का अनधिकृत कब्जा बढ़ता जा रहा है। उसके बाद भी भारत सरकार चीन के सामने बेबस नजर आ रही है। अब आर्थिक स्थिति को संभालना और महंगाई से निपटना भारत सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। वहीं अमेरिका, चीन, रूस के तीन पाटों के बीच में फंसकर भारत लगातार पिस रहा है। सभी महाशक्तियां भारत को अपने इशारे पर नचा रही हैं। भारत को उनके इशारों पर नाचना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति इसके पहले कभी नहीं थी। अब जिस तरह की आर्थिक मंदी की वैश्विक स्थिति बन रही है। उसने भारत की चिताओं को बढ़ा दिया है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार को वास्तविक सत्य के आधार पर अपनी नीतियां बनानी होगी। अहंकार से बाहर निकलना होगा। तभी जाकर स्थितियों में सुधार लाया जा सकता है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सोने और चांदी की कीमतों में नरमी

नई दिल्ली।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में नरमी आई है। सोना तीन हफ्तों से अधिक के निचले स्तर पर पहुँच गया है, जहाँ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर यह लगभग 2000 रुपये की गिरावट के साथ ही 1,49,904 प्रति ग्राम पर कारोबार कर रहा है। दूसरी ओर चांदी के भाव 3,549 रुपये नीचे आकर 2,26,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गये। इस तेज गिरावट के साथ ही सोना 1.50 लाख के स्तर पर पहुंच गया।

इस गिरावट के पीछे वैश्विक आर्थिक कारक और भू-राजनीतिक तनाव प्रमुख कारण रहे हैं। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण भी कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ने की आशंका गहरा गई है। इसके परिणामस्वरूप, अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना भी मजबूत हुई है, जिसका सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ा है। आमतौर पर महंगाई बढ़ने पर सोने को सुरक्षित निवेश माना जाता है, लेकिन जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो सोने में निवेश कम हो जाता है, क्योंकि इससे कोई ब्याज या नियमित आय प्राप्त नहीं होती।घरेलू सर्राफा बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों पर इसका असर साफ देखा गया। दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 15,423 प्रति ग्राम, 22 कैरेट का भाव 14,319 प्रति ग्राम और 18 कैरेट का दाम 11,571 प्रति ग्राम पर आ गया है। वहीं, 22 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 1,63,108 रुपये पर दर्ज की गई। चांदी की बात करें तो, दिल्ली में यह 245 प्रति ग्राम पर आ गई है, जिसमें 5 की गिरावट है, जबकि प्रति किलोग्राम 2,45,000 रुपये पर कारोबार कर रही है, जो 5,000 की बड़ी गिरावट दर्शाता है। सिर्फ सोना-चांदी ही नहीं, बल्कि प्लैटिनम और पैलेडियम जैसी अन्य कीमती धातुओं पर भी वैश्विक स्तर पर दबाव देखा गया, जिनकी कीमतों में लगभग 1 फीसदी तक की गिरावट आई है।

कैनरा बैंक की 555 दिन की एफडी में वरिष्ठ नागरिकों को 7.10फीसदी मिल रहा उच्च ब्याज

नई दिल्ली,।

कैनरा बैंक ने अपनी 555 दिनों की विशेष एफडी योजना में आकर्षक ब्याज दरें पेश की हैं, खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए। इस खास एफडी योजना में वरिष्ठ नागरिकों को सालाना 7.10फीसदी का उच्च ब्याज मिल रहा है, जिसका वार्षिक आधार पर मिलने वाला प्रतिफल लगभग 7.29फीसदी है। वहीं, सामान्य ग्राहकों को इस अवधि की एफडी पर 6.60फीसदी सालाना ब्याज दिया जा रहा है, जिसका वार्षिक प्रतिफल करीब 6.77फीसदी है। यह योजना उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो करीब डेढ़ साल की अवधि के लिए अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं।उदाहरण के लिए यदि कोई वरिष्ठ नागरिक एक लाख रुपए की 555 दिन की एफडी कराता है, तो उसे करीब 7,100 रुपए का सालाना ब्याज प्राप्त होगा, जबकि वार्षिक प्रतिफल के आधार पर यह करीब 7,290 रुपए के बराबर होगा। सामान्य ग्राहकों के लिए समान राशि पर करीब 6,600 रुपए का सालाना ब्याज बनेगा। यह अतिरिक्त ब्याज दर वरिष्ठ नागरिकों को समान निवेश पर बेहतर रिटर्न सुनिश्चित करती है। इसके अतिरिक्त यदि कोई ग्राहक एक करोड़ रुपए से ज्यादा की बड़ी राशि जमा करना चाहता है, तो बैंक नॉन-कॉलेबल एफडी का विकल्प भी प्रदान करता है। इसमें सामान्य ग्राहकों को 6.70फीसदी और वरिष्ठ नागरिकों को 7.20फीसदी तक का सालाना ब्याज मिल सकता है। नॉन-कॉलेबल एफडी में आमतौर पर समय से पहले पैसा निकालने की सुविधा नहीं होती है, जिसके कारण इसकी ब्याज दर सामान्य एफडी से थोड़ी ज्यादा होती है। इसके विपरीत, कॉलेबल एफडी में नियमों के तहत समय से पहले निकासी संभव है, हालांकि इस पर कुछ शुल्क या ब्याज कटौती लागू हो सकती है। निवेश करने से पहले बैंक की नवीनतम शर्तों और ब्याज दरों की पुष्टि करना अहम है। एफडी से होने वाली आय पर कर लागू होता है और कुछ मामलों में बैंक टीडीएस भी काट सकता है, इसलिए अपनी कर स्थिति का भी ध्यान रखना चाहिए। कैनरा बैंक की यह 555 दिन की एफडी उन निवेशकों के लिए एक मजबूत विकल्प है जो सुरक्षित निवेश, निश्चित रिटर्न और शेयर बाजार के जोखिमों से बचाव चाहते हैं।

अन्नु प्रोजेक्ट्स की लिस्टिंग इश्यू प्राइस से 27 फीसदी नीचे रहा

निवेशक को हर लॉट पर करीब 4077 रुपए का हुआ नुकसान

नई दिल्ली।

अन्नु प्रोजेक्ट्स की लिस्टिंग ने उम्मीद के उलट नतीजा दिया, क्योंकि बुधवार को इसके शेयरों की लिस्टिंग इश्यू प्राइस से 27 फीसदी नीचे हुई। इस लिहाज से आईपीओ में एक लॉट पाने वाले निवेशक को हर लॉट पर करीब 4077 रुपए का नुकसान हुआ। यानी जिन्होंने 14,949 रुपए लगाए थे वो घटकर 10,872 रुपए रह गया है।अन्नु प्रोजेक्ट्स का शेयर इश्यू प्राइस 99 रुपए के मुकाबले एनएसई पर 72 रुपए पर लिस्ट हुआ। इस तरह हर शेयर पर 27 रुपए का नुकसान हुआ। वहीं, बीएसई पर शेयर की लिस्टिंग 75 रुपए पर हुई, जो इश्यू प्राइस से 24.24 फीसदी कम है। बीएसई के लिस्टिंग भाव के हिसाब से एक लॉट की कीमत घटकर 11,325 रुपए रह गई। इस तरह निवेशक को एक लॉट पर 3,624 रुपए का नुकसान हुआ। अन्नु प्रोजेक्ट्स के आईपीओ को कुल 5.18 करोड़ शेयरों के लिए आवेदन मिले थे, जबकि कंपनी ने 1.76 करोड़ शेयर बिक्री के लिए रखे थे। इस तरह आईपीओ कुल 2.93 गुना भरा।

गैर-संस्थागत निवेशकों का हिस्सा सबसे ज्यादा 3.55 गुना भरा। खुदरा निवेशकों के लिए रखा गया हिस्सा 2.68 गुना और पात्र संस्थागत खरीदारों का हिस्सा 1.72 गुना भरा।अन्नु प्रोजेक्ट्स का 175.06 करोड़ रुपए का आईपीओ पूरी तरह नए शेयरों पर आधारित था।

इसमें प्रमोटर या मौजूदा निवेशक की तरफ से शेयर बिक्री यानी ऑफर फॉर सेल शामिल नहीं था। कंपनी ने 1.76 करोड़ नए शेयर जारी किए। आईपीओ का प्राइस बैंड 94 से 99 रुपए प्रति शेयर था और एक लॉट में 151 शेयर रखे गए थे। आईपीओ से मिली रकम में से 115 करोड़ रुपए कंपनी की कार्यशील पूंजी की जरूरतों पर खर्च किए जाने हैं।

करीब 15.41 करोड़ से मशीन और उपकरण खरीदे जाएंगे। बची रकम का इस्तेमाल सामान्य कारोबारी जरूरतों के लिए किया जाएगा।बता दें साल 2003 में बनी अन्नु प्रोजेक्ट्स बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से जुड़ी कंपनी है। यह टेलीकॉम, सीवरेज, गैस पाइपलाइन और रेलवे सिग्नलिंग से जुड़े प्रोजेक्ट पर काम करती है। टेलीकॉम बिजनेस में कंपनी केबल और टावर से जुड़े बुनियादी ढांचे का सर्वे, डिजाइन और इंस्टॉलेशन करती है।

किआ सोरेंटो की नई एसयूवी 4 सितंबर को होगी लॉन्च

नई दिल्ली । भारतीय बाजार में किआ सोरेंटो की नई प्रमुख एसयूवी के रूप में 4 सितंबर को लॉन्च होने जा रही है। मजबूत हाइब्रिड संस्करण में 1.6 लीटर इंजन दिया जाएगा, जो 238 हॉर्सपावर की ताकत और 380 न्यूटन मीटर का अधिकतम टॉर्क पैदा करेगा। यह एसयूवी मजबूत हाइब्रिड और डीजल, दोनों इंजन विकल्पों के साथ उतारी जाएगी। वहीं, 2.0 लीटर डीजल इंजन 202 हॉर्सपावर की ताकत और 441 न्यूटन मीटर का टॉर्क देगा, जिससे यह परफॉर्मेंस के मामले में भी काफी दमदार होगी। सोरेंटो के बाहरी डिजाइन में किआ की सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल प्रमुखता से दिखेगी। इसके साथ बड़े और सीधे आकार के एलईडी हेडलैंप दिए गए हैं, जिनमें वाई-आकार की एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट्स मिलती हैं। आगे की तरफ एलईडी फॉग लैंप और बंपर के किनारों पर वर्टिकल एयरो वेंट भी दिए गए हैं, जो इसकी स्पोर्टी अपील को बढ़ाते हैं। कंपनी ने अभी मिश्रधातु पहियों का आकार आधिकारिक तौर पर नहीं बताया है, लेकिन इसमें 19 इंच के आकर्षक पहिए मिलने की संभावना है। पीछे की तरफ चौकोर आकार के टेल-लैंप, उल्टे एल-आकार की एलईडी लाइट सिग्नेचर, एक बड़ा रूफ स्पॉयलर और दो रंगों वाला बंपर डिजाइन इसे आधुनिक और प्रीमियम लुक देता है। केबिन के अंदर भी सोरेंटो को एक आधुनिक और शानदार रूप दिया गया है। सामने की तरफ एक जुड़ा हुआ डिस्प्ले पैनल दिया गया है, जिसमें मनोरंजन प्रणाली और चालक सूचना प्रणाली के लिए दो बड़ी स्क्रीन शामिल हैं। माना जा रहा है कि दोनों स्क्रीन 12.3 इंच की होंगी।

शेयर बाजार गिरावट पर बंद

सेंसेक्स 373, निफ्टी 141अंक गिरा

मुम्बई ।

भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को भी गिरावट रही। गत दिवस भी बाजार गिरावट पर बंद हुआ था। आज बाजार में ये गिरावट दुनिया भर से मिले कमजोर संकेतों के साथ ही बिकवली हावी रहने से आई है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के साथ ही कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिकी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका से भी निवेशक बाजार से दूर हुए हैं। इससे भी वह टूटा है। दिनभर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 373.93 अंक गिरकर 76,570.35 पर आ गया। वहीं 50 शेयरों वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 141.35 अंक नीचे आकर 23,914.45 पर बंद हुआ। आज कारोबार के दौरान करीब 2323 शेयरों में गिरावट रही जबकि 1827 शेयरों में बढ़त दर्ज की गयी। वहीं 191 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। निफ्टी में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज करने वाले शेयरों में आयशर मोटर्स, विप्रो, बजाज ऑटो, एशियन पेंट्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा (एमएंडएम) शामिल थे, जिन्होंने निवेशकों को निराश किया। इसके विपरीत, कोल इंडिया, अदाणी पोर्ट्स, बजाज फिनसर्व, अदाणी एंटरप्राइजेज और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स जैसे कुछ शेयरों ने बढ़त हासिल कर बाजार को संभालने का प्रयास किया।

बाजार पर दबाव डालने वाले प्रमुख कारकों में वैश्विक कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें शामिल थीं। बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 1 फीसदी बढ़कर 95.4 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गईं। इसके अलावा अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा जल्द ही ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका के कारण वैश्विक बॉन्ड यील्ड ऊंचे बने हुए हैं। अमेरिकी ब्याज दरों में वृद्धि से वैश्विक निवेशकों के लिए भारत जैसे उभरते हुए बाजार कम आकर्षक हो जाते हैं, जिससे विदेशी पूंजी का बहिर्प्रवाह बढ़ने का जोखिम रहता है। इससे भी घरेलू बाजार पर प्रभाव पड़ा है। कमजोर वैश्विक संकेतों ने भी भारतीय बाजार पर नकारात्मक असर डाला। एशियाई बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली; दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक 3 फीसदी से अधिक गिरा, जबकि जापान का निक्केई 225 इंडेक्स भी लगभग 3 फीसदी नीचे आया। चीन का शंघाई एसएसई कंपोजिट इंडेक्स और हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स भी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे, जिसने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता को उजागर किया और भारतीय निवेशकों के बीच चिंता पैदा की। वहीं इससे पहले आज सुबह बाजार गिरावट पर खुला। इसके बाद सेंसेक्स 700 अंक टूटकर 76,243 के स्तर पर पहुंच गया जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी भी 23900 अंक तक गिरा। ये 230 अंकों की गिरावट के साथ ही 23,800 अंक तक नीचे आया।

रुपया गिरावट पर बंद

मुंबई ।

भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले दो पैसे की गिरावट के साथ ही 94.97 पर बंद हुआ, जो अपने पिछले बंद भाव 94.95 प्रति डॉलर से मामूली रूप से कमजोर था। वहीं अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में गत दिवस शुरुआती कारोबार के दौरान भारतीय रुपये में 26 पैसे की तेजी दर्ज की गई। 95.06 के स्तर पर खुलने के बाद यह मजबूत होकर 94.96 प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि डॉलर के मुकाबले रुपये को निकट अवधि में 95.10-95.20 के आसपास मजबूत समर्थन मिलता दिख रहा है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 95.06 प्रति डॉलर पर खुला। इसके बाद इसमें तेजी आई और यह 26 पैसे की बढ़त दर्ज करते हुए 94.96 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। रुपये ने सोमवार को शुरुआती नुकसान की भरपाई की और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 21 पैसे की बढ़त के साथ 95.22 पर बंद हुआ था।

एथर एनर्जी जल्द लांच करेगी अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर कोनार्क

नई दिल्ली।

आगामी 29 अगस्त को एथर एनर्जी कंपनी बेंगलुरु में अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर कोनार्क लॉन्च करने जा रही है। कोनार्क को एथर के बिल्कुल नए ईएल प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, जो इस प्लेटफॉर्म पर निर्मित होने वाला पहला मॉडल है। यह वाहन कंपनी के पोर्टफोलियो में एक महत्वपूर्ण विस्तार होगा, जिसका उद्देश्य व्यापक ग्राहक वर्ग तक अपनी पहुंच बनाना है। कंपनी ने इसके उत्पादन के लिए छत्रपति संभाजीनगर में एक नई निर्माण इकाई भी स्थापित की है। एथर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने इस उपलब्धि को हीरो मोटोकॉर्प के अध्यक्ष पवन मुंजाल के साथ साझा किया, जिन्होंने 2016 में शुरुआती चरण में ही इसमें निवेश किया था। कोनार्क धातु यानी मेटल बॉडी के साथ बाजार में आएगा, जिसकी बनावट मजबूत और दैनिक उपयोग के लिए अनुकूल होगी। इसका डिजाइन पारिवारिक जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें हैंडलबार पर मुख्य लाइट, एक लंबी व सपाट सीट और सामान रखने के लिए समतल फुटबोर्ड जैसी सुविधाएं हैं। इसमें दो से पांच किलोवाट-घंटा क्षमता तक के बैटरी विकल्प मिल सकते हैं, जो एक बार चार्ज होने पर 100 से 150 किलोमीटर तक की दूरी तय करने में सक्षम होगा। लागत नियंत्रण और मजबूती के लिए इसमें एलएफपी बैटरी तकनीक का उपयोग होने की संभावना है। यह नया ईवी स्कूटर एथर की रिज्टा श्रृंखला से नीचे के वर्ग में रखा जाएगा, जिससे यह अधिक किफायती कीमत पर उपलब्ध हो सकेगा। बाजार में यह टीवीएस आईक्यूब, बजाज चेतक, हीरो विडा और ओला एस1 जैसे स्थापित मॉडलों को सीधी टक्कर देगा।

टाटा मोटर्स हिस्सेदारी में सबसे ज्यादा बढ़त हासिल करने वाली कंपनी बनी

जनवरी-अगस्त 2026 में यात्री वाहन बाजार में दूसरे नंबर पर पहुंची

नई दिल्ली,।

टाटा मोटर्स बाजार हिस्सेदारी में सबसे ज्यादा बढ़त हासिल करने वाली कंपनी बन गई है। साल 2026 के शुरुआती आठ महीने में उसने यह बढ़त हासिल की। कंपनी के सामान्य ईंधन वाले पोर्टफोलियो में जबरदस्त वृद्धि ने इस बिक्री में सबसे ज्यादा योगदान किया, जबकि इलेक्ट्रिक वाहन कारोबार ने भी खासा सुधार दर्ज किया गया। लिहाजा, टाटा की बाजार हिस्सेदारी 12.62 फीसदी से बढ़कर 14.29 फीसदी हो गई। छह प्रमुख विनिर्माताओं में यह सबसे ज्यादा बढ़ोतरी थी।

इस वृद्धि की वजह से टाटा जनवरी-अगस्त 2026 में यात्री वाहन बाजार में दूसरे पायदान पर पहुंच गई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में वह चौथे नंबर पर थी। जनवरी-अगस्त 2025 में दूसरे पायदान वाली महिंद्रा ऐंड महिंद्रा खिसककर तीसरे स्थान पर आ गई, जबकि ह्युंडै चौथे नंबर पर पहुंच गई।

'वाहन' के पंजीकरण आंकड़ों के मुताबिक टाटा की कंपनी ने जनवरी से अगस्त 2026 के बीच 4,94,370 यात्री वाहनों का पंजीकरण किया। यह संख्या पिछले साल इसी अवधि में पंजीकृत 3,60,245 वाहनों के मुकाबले 37.2 फीसदी ज्यादा रही। यह आंकड़ा समूचे यात्री वाहन बाजार की 21.2 फीसदी की वृद्धि से काफी बेहतर रहा, जो इसी अवधि में दर्ज 28.5 लाख से बढ़कर 34.6 वाहन लाख हो गया। यह वृद्धि केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के बल पर नहीं आई थी। ईवी को छोड़कर टाटा का पंजीकरण 3,13,789 की तुलना में करीब 30.1 फीसदी बढ़ा और 4,08,188 वाहन हो गया।

केंद्र और राज्य सरकारों ने अगस्त में 1.68 लाख करोड़ का राजस्व प्राप्त किया

सरकार ने खपत मांग बढ़ाने पिछले साल जीएसटी दरों में किया था बदलाव

नई दिल्ली,।

केंद्र और राज्य सरकारों ने अगस्त में 1.68 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध जीएसटी राजस्व प्राप्त किया। यह रकम पिछले अगस्त की तुलना में 8.3 फीसदी ज्यादा है जबकि उस दौरान कर की दर अपेक्षाकृत ज्यादा थी। सरकार ने खपत मांग को बढ़ाने के लिए पिछले साल सितंबर में जीएसटी दरों में बदलाव किया था। रिफंड से पहले का सकल जीएसटी संग्रह अगस्त में 1.99 लाख करोड़ रुपए रहा जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 14.8 फीसदी ज्यादा है।

रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में केंद्र और राज्य सरकारों ने 1.81 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध जीएसटी संग्रह अर्जित किया था। उस दौरान 29,968 करोड़ रुपए का कर रिफंड जारी किया गया था। व्यापारियों को उनके निर्यात पर लगने वाले कर का रिफंड मिलता है जबकि घरेलू आपूर्तिकर्ता अपने इस्तेमाल न किए गए कर क्रेडिट के लिए रिफंड का दावा करते हैं। अगस्त भी आयात से प्राप्त जीएसटी संग्रह की वृद्धि घरेलू कारोबार के मिले राजस्व की तुलना में ज्यादा रही। घरेलू जीएसटी राजस्व सालाना आधार पर 9.3 फीसदी बढ़कर 1.37 लाख करोड़ रुपए रहा जबकि आयात से मिलने वाला जीएसटी राजस्व 29 फीसदी बढ़कर 62,604 करोड़ रुपए रहा। ईवाई इंडिया के टैक्स पार्टनर ने कहा कि आयात से जुड़ी जीएसटी संग्रह में वृद्धि दर्शाती है कि कुछ क्षेत्रों में अभी भी बाहरी आपूर्ति पर निर्भरता बनी हुई है। इससे इन क्षेत्रों में ज्यादा स्थानीयकरण और आयातित वस्तुओं की जगह घरेलू उत्पाद को अपनाए जाने के लिए कुशल नीति की जरूरत का पता चलता है। अगस्त में जीएसटी रिफंड सालाना आधार पर 68 फीसदी बढ़कर 31,795 करोड़ रुपए रहा। इसमें घरेलू रिफंड करीब 73 फीसदी बढ़कर 18,490 करोड़ रहा और आयातित उत्पादों के मामले में जीएसटी रिफंड करीब 62 फीसदी बढ़कर 13,305 करोड़ रुपए रहा।

भारत और वर्ल्ड बैंक डिजिटल और टूरिज्म हब पर एक साथ करेंगे काम

वित्त मंत्री सीतारमण ने भारत के वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जुड़ाव का किया स्वागत

एशविले,।

भारत और वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म और प्राइवेट कैपिटल जुटाने पर ज्यादा रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जी20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में एशविले में वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अध्यक्ष अजय बंगा से मुलाकात की। बैठक के बाद जारी बयान में इसकी जानकारी दी गई। बयान के मुताबिक वित्त मंत्री सीतारमण ने भारत के साथ वर्ल्ड बैंक ग्रुप के लगातार जुड़ाव का स्वागत किया। उन्होंने 1.5 अरब डॉलर के डेवलपमेंट पॉलिसी फाइनेंसिंग को तेजी से प्रोसेस करने के लिए आभार जताया।

रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्री ने आईएफसी के उस सहयोग का भी स्वागत किया, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए एमएसएमई सेक्टर को दिया गया है।

बयान में कहा गया कि यह मदद रिकॉर्ड समय में प्रोसेस की गई और इसका भारत के एमएसएमई सेक्टर पर सकारात्मक असर पड़ा है। बैठक में भारत-वर्ल्ड बैंक ग्रुप पार्टनरशिप को मजबूत करने और फाइनेंसिंग टूल्स के ज्यादा इस्तेमाल पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने भारत में मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी की बड़ी भूमिका पर बात की।

इस प्रस्तावित सहयोग के तहत गारंटी के व्यवस्थित इस्तेमाल और ज्यादा प्राइवेट पूंजी जुटाकर देश के कॉर्पोरेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और म्युनिसिपल बॉन्ड मार्केट को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेक्टर-बेस्ड, प्रोग्रामेटिक अप्रोच पर भी विचार किया।

इस तरह की व्यवस्था से साझेदारी का फोकस अलग-अलग प्रोजेक्ट से हटकर बड़े सेक्टर्स के प्रोग्राम पर होगा।

चीन ने जी20 बैठक में व्यापार असंतुलन पर आम सहमति बनने से रोका

वाशिंगटन,

अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने घोषणा की है कि चीन ने जी20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक में व्यापार असंतुलन और गैर-बाजार आर्थिक नीतियों पर आम सहमति बनने से रोक दिया। उत्तरी कैरोलिना के ऐशविले में हुई दो दिवसीय बैठक के बाद बेसेंट ने बताया कि चीन ने उन प्रस्तावों पर आपत्ति जताई जो अत्यधिक बाहरी अधिशेष और निर्यात पर अत्यधिक निर्भरता पैदा करने वाली नीतियों को लक्षित कर रहे थे। बेसेंट ने कहा कि यह स्पष्ट है कि दुनिया में सबसे ज्यादा और अस्थिर करंट अकाउंट सरप्लस वाला देश यानी चीन, इस बात से असहमत था। उन्होंने बताया कि बाकी 19 सदस्य देशों, जिनमें भारत भी शामिल था, उन्होंने चेयरमैन के उस बयान का समर्थन किया, जिसमें ऐसे देशों से नीतियों को हटाने की बात कही गई थी जिनका बाहरी अधिशेष बहुत ज्यादा है और वे घरेलू खपत को रोककर निर्यात पर अत्यधिक निर्भरता पैदा करती हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक बयान में चेतावनी दी गई थी कि बहुत ज्यादा और लगातार असंतुलन बाजारों को बाधित कर सकते हैं, आपूर्ति श्रृंखलाओं को कमजोर कर सकते हैं और अन्य अर्थव्यवस्थाओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसमें देशों से ऐसी गैर-बाजार नीतियों और तौर-तरीकों को खत्म करने का भी आग्रह किया था जो ऐसे असंतुलन को और बढ़ाते हैं। चीन ने विशेष रूप से ऊर्जा व्यापार और होर्मुज जलडमरूमध्य, वैश्विक आर्थिक असंतुलन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की निगरानी और सरकारी ऋण पुनर्गठन से जुड़े चार हिस्सों पर आपत्ति जताई है।बेसेंट ने जोर देकर कहा कि 19 देशों के बीच बनी यह सहमति उन अर्थव्यवस्थाओं के बारे में बढ़ती अंतरराष्ट्रीय चिंता को दर्शाती है जो सब्सिडी वाले उत्पादन और निर्यात पर ज्यादा निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि गैर-बाजार-आधारित अर्थव्यवस्थाओं द्वारा सस्ते निर्यात की कभी न खत्म होने वाली बाढ़ लाना टिकाऊ नहीं है। हालांकि उन्होंने इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं की कि क्या जी20 के अलग-अलग सदस्य देश इसके जवाब में टैरिफ या व्यापार से जुड़ी अन्य सुरक्षात्मक नीतियां लागू करेंगे। चेयरमैन के बयान में आईएमएफ से वैश्विक असंतुलन के कारणों की जांच मजबूत करने का भी आग्रह किया।

वैश्विक निवेशकों से पूंजी जुटाने की अनुमति देने की योजना पर हो रहा विचार

सेबी-आईएफएससीए ने इस योजना की रूपरेखा तैयार करने की कई बैठकें

नई दिल्ली,।

भारत की सूचीबद्ध कंपनियों को देसी एक्सचेंजों और गिफ्ट-आईएफएससी में दो जगहों पर सूचीबद्धता या डुअल-लिस्टिंग के जरिए वैश्विक निवेशकों से पूंजी जुटाने की अनुमति देने की योजना पर विचार किया जा रहा है। इस महीने सेबी और आईएफएससीए ने इस योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए कई बैठकें की हैं। दो साल से ज्यादा समय से चल रही इन चर्चाओं में अब प्रस्तावित ढांचे के प्रमुख तौर-तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इसमें सूचीबद्धता, भेदिया कारोबार, पुनर्खरीद तथा अधिग्रहण से संबंधित सेबी के नियमों में जरुरी बदलाव शामिल हो सकते हैं।

इस प्रक्रिया पर चर्चा करने वाली समिति में नियामक और बाजार अवसंरचना संस्थानों (एमआईआई) के सदस्य शामिल हैं।

सूत्रों के मुताबिक कंपनियों को प्रवासी भारतीयों और अन्य वैश्विक निवेशकों से डॉलर में पूंजी जुटाने की अनुमति मिल सकती है। हालांकि घरेलू निवेशकों को गिफ्ट सिटी में अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध इन प्रतिभूतियों में खरीद-बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। अच्छी बात यह है कि चर्चा में प्रगति हुई है।

गिफ्ट-आईएफएससी के जरिए से जुटाई गई पूंजी की निगरानी पर भी विचार किया जा रहा है, जिसमें गिफ्ट सिटी में संरक्षक अहम भूमिका निभा सकते हैं। जिन अन्य पहलुओं पर विचार किया जा रहा है, उनमें गिफ्ट-आईएफएससी में न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता, मुद्रा में उतार-चढ़ाव, निवेशकों की भागीदारी का दायरा और कर संबंधी प्रभाव शामिल हैं।जेएसए एडवोकेट्स ऐंड सॉलिसिटर्स में पार्टनर ने कहा कि भारतीय सूचीबद्ध कंपनियों को घरेलू ढांचे के तहत न्यूनतम 25 फीसदी सार्वजनिक शेयरधारिता बनाए रखना जरूरी है। आईएफएससी अपने लिए अलग न्यूनतम सार्वजनिक प्रस्ताव की आवश्यकताएं तय करता है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

ईशांत शर्मा: कपिल देव के बाद टेस्ट में भारत के दूसरे सफलतम तेज गेंदबाज

पांच साल से पहले खेला आखिरी मैच

नई दिल्ली । भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा को उनकी लंबाई और निरंतरता के साथ 150 के आस-पास की गति के साथ गेंदबाजी के लिए जाना जाता है। ईशांत टेस्ट क्रिकेट में भारत के छठे सबसे सफल गेंदबाज हैं। वहीं कपिल देव के बाद टेस्ट क्रिकेट में भारत के दूसरे सबसे सफल तेज गेंदबाज हैं। ईशांत शर्मा का जन्म 2 सितंबर 1988 को दिल्ली में हुआ था। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने 2006 में दिल्ली के लिए डेब्यू किया। छह फीट चार इंच लंबे ईशांत शर्मा के पास वह सारी क्षमताएं थी, जो एक तेज गेंदबाज में होनी चाहिए। उनके पास गति के अलावा, स्विंग, और बाउंस था, जो विपक्षी बल्लेबाजों के लिए हमेशा मुश्किल खड़ी करता था। विराट कोहली, शिखर धवन, गौतम गंभीर जैसे दिग्गज क्रिकेटरों के साथ घरेलू क्रिकेट खेलने वाले ईशांत को मई 2007 में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में डेब्यू का मौका मिला। घरेलू क्रिकेट में पदार्पण के ठीक एक साल बाद भारतीय टीम में जगह बनाने वाले ईशांत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया और जल्द ही टेस्ट और वनडे फॉर्मेट में भारतीय तेज गेंदबाजी का

प्रमुख चेहरा बन गए। ईशांत ने देश और विदेश दोनों जगहों पर सफलता प्राप्त की। एमएस धोनी की कप्तानी में 2013 में इंग्लैंड को हराकर आईसीसी चैंपियस ट्रॉफी जीतने वाली टीम के ईशांत अहम सदस्य रहे।

शर्मा का व्यापक असर टेस्ट क्रिकेट में दिखा। विराट कोहली की कप्तानी में देश और विदेश में टेस्ट में भारतीय टीम को मिली सफलता की एक वजह ईशांत की गेंदबाजी भी रही। शर्मा भारत के उन चुनिंदा क्रिकेटरों में शामिल हैं जिन्हें 100 टेस्ट खेलने की उपलब्धि हासिल हो सकी है।

38 साल के होने जा रहे ईशांत शर्मा ने भारतीय टीम के लिए 105 टेस्ट मैच, 80 वनडे और 14 टी20 मैच खेले हैं। टेस्ट मैचों में उनके 311, वनडे में 115 और टी20 में 8 विकेट दर्ज हैं। ईशांत नवंबर 2021 के बाद से भारतीय टीम के लिए नहीं खेले हैं।

ईशांत निश्चित रूप से अब भारतीय टीम की योजना में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अब तक संन्यास नहीं लिया है। वह आईपीएल में गुजरात टाइटंस का हिस्सा हैं।

लॉर्ड्स टेस्ट में करारी हार के बाद पाकिस्तान का बड़ा एक्शन

इंग्लैंड दौरे से 7 खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ की छुट्टी, माइक हेसन को कमान

लंदन। इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में 194 रनों की करारी शिकस्त और सीरीज में 0-2 से पिछड़ने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने कड़े कदम उठाए हैं। पीसीबी ने इंग्लैंड दौरे के बीच से ही अपनी लगभग आधी टीम बदलते हुए 7 प्रमुख खिलाड़ियों को स्वदेश वापस बुलाने का फैसला किया है। इसके साथ ही मुख्य कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल को भी पद से हटा दिया गया है। टीम से बाहर किए गए 7 खिलाड़ी और उनके रिप्लेसमेंट पीसीबी के आधिकारिक बयान के अनुसार, खराब प्रदर्शन के चलते बाहर किए गए खिलाड़ियों की जगह नए खिलाड़ियों को तीसरे टेस्ट से पहले इंग्लैंड भेजा जा रहा है।

वापस बुलाए गए खिलाड़ी (7): मोहम्मद रिज़वान, इमाम-उल-हक़, सलमान अली आग़ा, आमिर जमाल, खुर्रम शहज़ाद, अली उस्मान और ओवैस ज़फर।

नए शामिल खिलाड़ी (7): साइम अयूब, अब्दुल्ला फ़ज़ल, अराफ़ात मिन्हास, इमरान जूनियर, साद बेग, इमरान रंधावा और रज़ाउल्लाह।

कोचिंग स्टाफ में बड़ा फेरबदल: माइक हेसन को टेस्ट की भी कमान

सरफराज और उमर गुल की छुट्टी: मुख्य कोच सरफराज अहमद और बॉलिंग कोच उमर गुल की छुट्टी कर दी गई है।

हेसन और नोफ्के को जिम्मेदारी: सीमित ओवरों (व्हाइट-बॉल) के मुख्य कोच माइक हेसन को अब टेस्ट (रेड-बॉल) टीम का भी मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। वहीं एशले नोफ्के को टीम का नया गेंदबाजी कोच बनाया गया है।

भारत दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया ए टीम घोषित

हैंड्सकॉम्ब, सैम कोंस्टास को मौका

नई दिल्ली । क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारत ए टीम के खिलाफ होने वाली दो चार दिवसीय, और तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ए टीम की घोषणा कर दी गई है। पीटर हैंड्सकॉम्ब को ऑस्ट्रेलिया ए टीम में जगह मिली है। इससे उनके टेस्ट करियर को एक और मौका मिल सकता है। टीम में ब्रेंडन डॉगेट और झाई रिचर्डसन भी हैं। ऑस्ट्रेलिया ए इस महीने के आखिर में दौरे के चार दिवसीय मैचों के लिए पुडुचेरी जाएगी, जिसके बाद तीन 50-ओवर के मैच होंगे। भारत ए के खिलाफ सीरीज बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी से पहले दौरे पर आ रहे कई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के पास सीनियर टीम में जगह बनाने का यह मौका है। 35 साल के हैंड्सकॉम्ब चार दिन की टीम में सबसे उम्रदराज और सबसे अनुभवी खिलाड़ी

हैं। दाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने 2023 में ऑस्ट्रेलिया के पिछले बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी टूर के सभी चार टेस्ट में खेलने के बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है और न ही ऑस्ट्रेलिया ए के लिए खेला है। आने वाले महीनों में ऑस्ट्रेलिया के भारत लौटने के साथ, यह टूर उन्हें सीनियर टीम में वापसी की दावेदारी का मजबूत मौका देता है। ऑस्ट्रेलिया सबकॉन्टिनेंटल कंडीशन के लिए अपने तेज गेंदबाजी विकल्प को देख रहा है, इसलिए डॉगेट और रिचर्डसन पर भी ध्यान देने की संभावना है। रिचर्डसन कंधे की कई बड़ी सर्जरी के बाद प्रथम श्रेणी क्रिकेट में लौटे हैं, जबकि टॉड मर्फी, सैम कॉन्स्टास और नाथन मैकस्वीनी उन नौ खिलाड़ियों में शामिल हैं जो पिछले साल लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया ए के चार-दिवसीय मैचों से लौटे हैं। युवा तेज गेंदबाज महली बियर्डमैन स्पेंसर जॉनसन के साथ वन-डे टीम में हैं।'

आईसीसी रैंकिंग

विमेंस एशिया कप में ऑलराउंडर प्रदर्शन, टी20 करियर की बेस्ट रैंकिंग पर पहुंचीं अट्टापट्टू

दुबई । विमेंस एशिया कप 2026 में शानदार प्रदर्शन के साथ श्रीलंकाई कप्तान चामरी अट्टापट्टू आईसीसी विमेंस टी20 प्लेयर रैंकिंग में तीनों कैटेगरी में अपने करियर की बेस्ट रेटिंग प्वाइंट्स तक पहुंच गई हैं। अट्टापट्टू ने 29 अगस्त को यूएई के खिलाफ ऑलराउंड प्रदर्शन किया। उन्होंने 25 गेंदों में नाबाद 48 रन बनाए। बतौर गेंदबाज 3 ओवरों में 10 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। कप्तान के इस प्रदर्शन की बदौलत टीम ने 9 विकेट से शानदार जीत हासिल की। इस नतीजे से अट्टापट्टू बल्लेबाजों की रैंकिंग में 734 रेटिंग प्वाइंट्स, गेंदबाजों में 552 और ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में 405 प्वाइंट्स के साथ अपने करियर की सबसे बेहतरीन स्थिति में

पहुंच गई। वह टी20 बल्लेबाजों में छठे स्थान पर बनी हुई हैं, जबकि गेंदबाजी सूची में तीन स्थान ऊपर चढ़कर 33वें स्थान पर पहुंच गई हैं और ऑल-राउंडर्स में तीसरे स्थान पर बरकरार हैं। अट्टापट्टू का यह प्रदर्शन इस साल की शुरुआत में आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में उनके अच्छे प्रदर्शन के बाद आया है, जहां उन्होंने श्रीलंका के लिए 172 रन बनाए थे और तीन विकेट लिए थे। उनकी ओपनिंग पार्टनर इमेशा दुलानी ने भी लेटेस्ट अपडेट में काफी सुधार किया है। यूएई के खिलाफ 18 गेंदों पर 25 रन की पारी खेलने वाली दुलानी चार स्थान ऊपर चढ़कर 625 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ 18वीं रैंकिंग पर पहुंच गई हैं। वहीं, हर्षिता समरविक्रमा बल्लेबाजों में एक स्थान ऊपर चढ़कर 23वें स्थान पर आ गई हैं। श्रीलंकाई गेंदबाजों को भी टूर्नामेंट के अपने शानदार ओपनिंग मैच का फायदा मिला है। मिताली अयोध्या ने 14 रन देकर तीन विकेट लिए, जिससे यूएई का स्कोर 79 रन तक सीमित रहा और वह 18 स्थान ऊपर चढ़कर 70वें स्थान पर पहुंच गई; साथ ही उनके 444 प्वाइंट्स भी उनके करियर का बेस्ट स्कोर है।

काउंटी चैंपियनशिप में इंग्लिश काउंट टीम

सरे से जुड़े औकिब नबी

फ्रेंचाइजी के लिए खेलेंगे 3 मुकाबले

नई दिल्ली। हाल ही में भारतीय टीम में चुने गए तेज गेंदबाज औकिब नबी काउंटी चैंपियनशिप में इंग्लिश काउंटी टीम 'सरे' से जुड़ गए हैं, जिसके लिए 3 मैच खेलेंगे। 29 वर्षीय खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय घरेलू क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने टूर्नामेंट में 60 विकेट लिए और जम्मू-कश्मीर को उसका पहला खिताब जिताने में मदद की। नबी अब सरे के लिए यॉर्कशायर, ससेक्स और ग्लैमॉर्गन के खिलाफ होने वाले अगले तीन मुकाबलों में खेलेंगे। 'आईएएनएस' ने 28 अगस्त को खबर दी थी कि नबी के रविवार को सरे से जुड़ने और काउंटी चैंपियनशिप में खेलने की संभावना है। नबी सरे के लिए तीन मैच खेलेंगे, जिसकी शुरुआत 2 सितंबर को 'द ओवल' में यॉर्कशायर के खिलाफ मैच से होगी। इसके बाद क्रमशः 8 और 15 सितंबर को होव और 'द ओवल' में ससेक्स और ग्लैमॉर्गन के खिलाफ मैच होंगे।

इस मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने रविवार को 'आईएएनएस' को बताया, 'हां, सभी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद औकिब को इंग्लैंड जाने के लिए वीजा मिल गया है। माना जा रहा है कि वह आज नई दिल्ली से इंग्लैंड के लिए रवाना होंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा, तो वह 2 सितंबर से शुरू होने वाले मैच के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। इस दौरे का मुख्य मकसद भारतीय टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं के लिए यह देखना भी है कि क्या नबी इंग्लैंड में गेंद को अच्छी तरह से स्विंग करा सकते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड में होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए उन्हें रेड कूकाबुरा गेंद के साथ अनुकूल परिस्थितियों में ऐसा करने की जरूरत होगी।'

नबी को श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए चोटिल जसप्रीत बुमराह के स्थान पर चुना गया था, हालांकि उन्हें डेब्यू का मौका नहीं मिल सका, क्योंकि भारत दोनों मुकाबलों में दो तेज गेंदबाजों के साथ उतरा था।

विमेंस डीपीएल

नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स को हराया

नई दिल्ली । विमेंस दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के खिलाफ 2 रन से रोमांचक जीत दर्ज की। अब दोनों टीमें फाइनल मैच में बुधवार को फिर से आमने-सामने होंगी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने शुरुआती झटकों से उबरते हुए 5 विकेट खोकर 126 रन बनाए।

ओपनर नजमा 2 रन पर आउट हो गईं, जबकि शिवी शर्मा 3 रन पर आउट हुईं, जिससे टीम 12/2 के स्कोर पर दबाव में आ गई। इसके बाद कप्तान आयुषी सोनी ने 55 गेंदों पर नाबाद 62 रनों की अहम पारी खेली और सात चौकों की मदद से पारी को संभाला। अर्चना ने 14 गेंदों पर 21 रन बनाकर टीम को जरूरी गति दी, जबकि समायरा राघव ने 26 गेंदों पर 32 रनों का अहम योगदान दिया, जिसमें दो चौके और एक छक्का शामिल था।

साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के लिए रूपाली विश्व मोहन ने 23 रन देकर 2 विकेट लिए। इनके अलावा, मयूरी सिंह, तनिषा सिंह और एकता भड़ाना ने 1-1 विकेट निकाला। 126/5 के मामूली स्कोर का बचाव करते हुए, नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने अनुशासित गेंदबाजी की और तनावपूर्ण आखिरी ओवर में संयम बनाए रखते हुए साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स को 124/7 के स्कोर पर रोक दिया। भले ही साउथ दिल्ली की शुरुआत ठीक रही, लेकिन टीम के लिए कोई निर्णायक साझेदारी नहीं हुई।

प्रिया पुनिया ने 30 गेंदों पर सर्वाधिक 31 रन बनाए, जबकि तनीषा सिंह ने 24 रन और कप्तान श्वेता सहरावत ने 12 गेंदों पर 20 रन की पारी खेली।

वैभव, अभिमन्यु के साथ चमके मुकेश

'सेंट्रल' को 4 विकेट से हराकर फाइनल में 'ईस्ट जोन'

बेंगलुरु । ईस्ट जोन ने दलीप ट्रॉफी 2026 के 'सेमीफाइनल-1' में सेंट्रल जोन के खिलाफ मुकाबले के तीसरे दिन 4 विकेट से जीत दर्ज करते हुए फाइनल में जगह बना ली है। कुल 7 विकेट हासिल करने वाले मुकेश कुमार को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। अब फाइनल मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में 6 सितंबर से शुरू होगा, जिसमें ईस्ट जोन की भिड़ंत सेमीफाइनल-2 (नॉर्थ जोन बनाम साउथ जोन) की विजेता टीम से होगी। टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी सेंट्रल जोन ने पहली पारी में 266 रन बनाए। इस पारी में रिंकू सिंह ने सर्वाधिक 60 रन जड़े, जबकि आर्यन जुयाल ने 46 रन टीम के खाते में जोड़े। इनके अलावा, यश ठाकुर ने नाबाद 30 रन की पारी खेली। विपक्षी खेमे से मुकेश कुमार (56/3) और अभिजीत सरकार ने 3-3 विकेट निकाले, जबकि मोहम्मद शमी और कौनेन कुरैशी ने 2-2 विकेट चटकाए। इसके जवाब में ईस्ट जोन भी अपनी पहली पारी में 266 रन ही बना सकी। सलामी जोड़ी के रूप में वैभव सूर्यवंशी ने अभिमन्यु ईश्वरन के साथ पहले विकेट के लिए 153 गेंदों में 162 रन की साझेदारी की। वैभव 81 गेंदों में 7 छक्कों और इतने ही चौकों के साथ 92 रन बनाकर आउट हुए, जबकि अभिमन्यु ने 8 चौकों के साथ 69 रन की पारी खेली। इनके अलावा सुदीप कुमार ने 25 रन टीम के खाते में जोड़े। विपक्षी खेमे से हर्ष दुबे ने 4 विकेट झटके। आर्यन पांडे और यश ठाकुर को 3-3 विकेट हाथ लगे। सेंट्रल जोन की दूसरी पारी 158 रन पर सिमट गई। इस टीम ने 97 के स्कोर तक 8 विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद अरशद खान ने हर्ष दुबे के साथ 9वें विकेट के लिए 43 रन की साझेदारी करते हुए टीम को शर्मनाक स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश की। हर्ष 3 चौकों के साथ 24 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद अरशद (25) ने यश ठाकुर (नाबाद 4) के साथ 18 रन जोड़े। इस पारी में मुकेश कुमार ने 44 रन देकर 4 विकेट निकाले। इनके अलावा, मोहम्मद शमी ने 3 शिकार किए।

अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम घोषित

वैभव को मौका, बुमराह भी शामिल

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मुकाबलों की टी20 सीरीज के लिए मंगलवार को 15-सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया। श्रेयस अय्यर टीम की कमान संभालेंगे, जबकि तिलक वर्मा को उप-कप्तानी सौंपी गई है। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर से भारतीय टी20 टीम का हिस्सा हैं, जिन्होंने पिछले मौके को बखूबी भुनाया था। इस टीम में नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह और हर्षित राणा को फिटनेस के आधार पर शामिल किया गया है, लेकिन मध्यक्रम के विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह को मौका नहीं मिला। टीम में अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती जैसे नियमित खिलाड़ी शामिल हैं। हर्षित राणा की भी टीम में वापसी हुई है, जबकि जुलाई में जिम्बाब्वे में खेलने वाली टीम में कुछ बदलाव किए गए हैं। जिम्बाब्वे टी20 सीरीज में न चुने जाने के बाद संजू सैमसन की वापसी हुई है। नियमित तेज गेंदबाजों की वापसी से गेंदबाजी विभाग में भी बदलाव हुए हैं। अर्शदीप के साथ बुमराह और हर्षित शामिल हैं। प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा और मयंक यादव, जो सभी जिम्बाब्वे दौरे पर गई टीम का हिस्सा थे, इस बार टीम में जगह नहीं बना सके। हार्दिक पांड्या को भी टीम में जगह नहीं मिली है।

भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 सितंबर को वनडे सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा, जिसके बाद 15 सितंबर को दूसरा मुकाबला आयोजित होगा। सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच 17 सितंबर को खेला जाना है। तीनों मुकाबले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होंगे। वैभव सूर्यवंशी ने हाल ही में दलीप ट्रॉफी 2026 में अपना जलवा बिखेरा है। उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में ईस्ट जोन के लिए खेलते हुए सेंट्रल जोन के खिलाफ 92 और 40 रन की पारियां खेली थीं।

अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की टी-20 टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी*, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर*, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह*, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा*।

पाकिस्तान टीम का प्रदर्शन पिछले 70 सालों में सबसे खराब

ये खेल ही क्यों रहे: दानिश कनेरिया

नई दिल्ली । पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक बार फिर से अपने खराब प्रदर्शन की वजह से चर्चा में है। बाबर आजम की कप्तानी वाली पाकिस्तान टीम 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए इंग्लैंड में है। शुरुआती 2 टेस्ट गंवाकर पाकिस्तान सीरीज में 2-0 से पीछे है। सीरीज हारने के बाद पाकिस्तान टीम और मैनेजमेंट फिर से सवालों घेरे में है। पूर्व पाकिस्तानी स्पिनर दानिश कनेरिया का कहना है कि पिछले 70 साल में उन्होंने पाकिस्तान टीम की ऐसी दुर्दशा नहीं देखी। आईएएनएस से खास बातचीत में दानिश कनेरिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी, गेंदबाजी, कप्तानी, टीम चयन, चयनकर्ताओं और प्रबंधन से जुड़े अन्य विषयों पर बात की और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मौजूदा स्थिति को बेहद निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा, 'पिछले 70 साल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की स्थिति सबसे खराब है। हारना बुरा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान टीम के किसी भी खिलाड़ी द्वारा कोई संघर्ष या फिर जूझने की क्षमता दिखाई नहीं पड़ती। यह सबसे बुरी स्थिति है।'

कनेरिया ने कहा, 'पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। खिलाड़ी हों या चयनकर्ता किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली है।

इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद पीसीबी में 'भूचाल'

सेलेक्टर मिस्बाह-उल-हक ने इस्तीफा भेजा

नई दिल्ली । दूसरे टेस्ट में शर्मनाक हार के बाद सीरीज के बीच में ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने टीम में बड़े बदलाव किए, जिसके बाद मिस्बाह-उल-हक ने पाकिस्तान की पुरुष चयन समिति के सेलेक्टर पद से इस्तीफा देने की पेशकश कर दी है। मिस्बाह मार्च में बनी उस चार सदस्यीय चयन समिति का हिस्सा थे, जिसमें आकिब जावेद, सरफराज अहमद और असद शफीक भी शामिल हैं। हालांकि, 'क्रिकइन्फो' की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान ने चयन पैनल से इस्तीफा देने की पेशकश की है। पीसीबी ने अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है, लेकिन खबरों के मुताबिक मिस्बाह ने लाहौर में नेशनल क्रिकेट अकादमी में बैटिंग कंसल्टेंट के पद से भी इस्तीफा दे दिया है। पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ लंदन में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में 194 रन से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद सोमवार को पीसीबी ने टेस्ट टीम से 7 खिलाड़ियों के साथ हेड कोच और बॉलिंग कोच सरफराज खान और उमर गुल को हटाया।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

चीन में जन्मदर में तेज गिरावट 2025 में जन्मे 79.2 लाख बच्चे

बीजिंग, एजेंसी। चीन में आबादी बढ़ाने की कोशिशों के बावजूद जन्मदर में फिर गिरावट दर्ज की गई है। 2025 में देश में 79.2 लाख बच्चों का जन्म हुआ, जबकि इस दौरान 1.13 करोड़ लोगों की मौत हुई। इसके साथ चीन की प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर घटकर शून्य से 2.41 प्रति हजार नीचे पहुंच गई। यह आंकड़ा 2024 में दर्ज -0.99 प्रति हजार की तुलना में कहीं अधिक नकारात्मक है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग की ओर से शुक्रवार को जारी 2025 के स्वास्थ्य विकास संबंधी सांख्यिकीय बुलेटिन में यह जानकारी सामने आई।

अमेरिका में केरल की दो महिलाओं की हत्या

कैलिफोर्निया , एजेंसी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में केरलम की दो महिलाओं की हत्या कर दी गई। मृतक महिलाओं की दोस्त कोट्टयम की अनिला को हत्या के शक में अमेरिकी पुलिस की हिरासत में है। तीनों महिलाएं एक ही अपार्टमेंट में रहती थीं। आरोप है कि अनिला ने एन पर चाकू से हमला किया और बाद में कार से अंजना को टक्कर मार दी। मृतकाओं की पहचान त्रिशूर के मुडिक्कोड की रहने वाली अंजना और तिरुवनंतपुरम के केशवदासपुरम की रहने वाली एन मैथ्यू के तौर पर की गई। अंजना के रिश्तेदार विनोद के मुताबिक, अंजना 2021 में अमेरिका गई थीं। उनके पति विजीश और छह साल की बेटी सदमे में हैं।

अमेरिकी सेना मंत्री डैन ड्रिस्कॉल ने 18 महीने बाद पद से दिया इस्तीफा

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के सेना मंत्री डैन ड्रिस्कॉल ने 18 महीने तक पद पर रहने के बाद इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय 'व्हाइट हाउस' ने सोमवार को यह जानकारी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के दौरान किसी शीर्ष सैन्य अधिकारी के पद छोड़ने का यह ताजा मामला है। उपराष्ट्रपति जे डी वेंस के मित्र ड्रिस्कॉल के पद छोड़ने का कोई कारण नहीं बताया गया है लेकिन रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के साथ उनके तनाव की खबरें व्यापक रूप से सामने आती रही हैं। यह सैन्य नेतृत्व, खासकर थल सेना में लगातार हो रहे फेरबदल का ताजा मामला है 'व्हाइट हाउस' की प्रवक्ता एना केली ने एक बयान में कहा, ''मंत्री ड्रिस्कॉल ने ऐतिहासिक सैन्य अभियानों के दौरान उत्कृष्ट नेतृत्व प्रदान करके, सैन्य तैयारियों और मारक क्षमता पर फिर से जोर देकर, रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता में मदद करके तथा अन्य कार्यों के जरिये सेना विभाग में राष्ट्रपति ट्रंप के 'अमेरिका को फिर से मजबूत बनाने' के एजेंडे को आगे बढ़ाने में बेहद प्रभावी भूमिका निभाई है।'' उन्होंने कहा, ''कमांडर-इन-चीफ और युद्ध मंत्री के साथ मिलकर किए गए उनके काम की बदौलत अमेरिकी थल सेना पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली है।'' अमेरिकी थल सेना के एक अधिकारी ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया कि ड्रिस्कॉल ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सेना की मौजूदा स्थिति पर बातचीत की और अपना इस्तीफा सौंप दिया। अधिकारी को और कोई जानकारी नहीं दी। ड्रिस्कॉल के पद छोड़ने से पहले सेना में उनके एक सहयोगी को हटाया गया था और उस ड्रोन कार्यक्रम को भी वापस लिया गया था, जिसके वह प्रमुख समर्थक थे।

बांग्लादेश में हिंदू त्योहारों की छुट्टियां रद्द: भड़के अल्पसंख्यक, जन्माष्टमी पर नहीं रहेगी पहले जैसी रौनक?

ढाका, एजेंसी। जैसे-जैसे जन्माष्टमी के साथ अन्य हिंदू त्योहारों की समय नजदीक आ रहा है, बांग्लादेश में सरकार के प्रति हिंदुओं में रोष बढ़ता ही जा रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि बांग्लादेश सरकार ने जन्माष्टमी को मिलने वाला सरकारी अवकाशरद्द कर दिया है। ढाकेश्वरी मंदिर, चट्टग्राम, सिलहट समेत कई मंदिरों में जन्माष्टमी मनाई जानी है, लेकिन इस बार यहां जन्माष्टमी को आधिकारिक छुट्टी नहीं रहेगी। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक, इस वर्ष 2 जनवरी को ही बांग्लादेश में सरस्वती पूजा, जन्माष्टमी, दुर्गाष्टमी और बुद्ध पूर्णिमा की सरकारी छुट्टियां रद्द कर दी गईं। हिंदू जागृति समिति व इसकी अगुवाई में हिंदुओं ने इसका भारी विरोध किया है। हसीना के अपदस्थ होने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं की हिंसा के चलते ढाका, सिलहट, खुलना, कुमिला, जेसोर और मीरपुर में बड़े-बड़े जुलूस नहीं निकाले जा रहे हैं इस बार भी यहां उत्साह फीका रहेगा।

समुद्र का जलस्तर बढ़ने से कोलकाता और मुंबई के लाखों लोग हो सकते हैं प्रभावित : यूएन

वाशिंगटन, एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि समुद्र का जलस्तर बढ़ने से कोलकाता और मुंबई में रह रहे लाखों लोग बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। सोमवार को जारी रिपोर्ट में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का जलस्तर बढ़ने के असर को लेकर कई गंभीर चेतावनियां दी गई हैं। ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर और बर्फ की परतें पिघलती हैं और पानी गर्म होता है, जिससे संपत्ति, लोगों और यहां तक ??कि संस्कृतियों पर भी असर पड़ता है। पैसिफिक आइलैंड्स फोरम लीडर्स की 55वीं बैठक में सेक्रेटरी-जनरल अमीना मोहम्मद ने जो रिपोर्ट जारी की, उसके मुताबिक 2024 में समुद्र के जलस्तर में सालाना बढ़ोतरी अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है और यह लगभग छह मिलीमीटर दर्ज की गई है।

इस बैठक की मेजबानी पलाऊ कर रहा है, जो प्रशांत महासागर के द्वीपों का एक देश है। समुद्र का जलस्तर बढ़ने से इसके कई द्वीप काफी हद तक डूब सकते हैं। यह बैठक इसी गंभीर खतरे को उजागर कर रही है।

रिपोर्ट में कहा गया है, 'दक्षिण एशिया के निचले डेल्टा इलाकों और भारत के कोलकाता और मुंबई व बांग्लादेश के ढाका जैसे शहरों में सबसे बड़ा असर लोगों के विस्थापन के रूप में दिख रहा है। यहां 1.4 करोड़ से अधिक लोगों के घर हमेशा के लिए पानी में डूबने का खतरा है। ' रिपोर्ट में इस डरावनी स्थिति के होने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा तय नहीं की गई है। न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में असिस्टेंट सेक्रेटरी-जनरल नाविद हनीफ ने कहा कि समुद्र का बढ़ता जलस्तर एक चुनौती पेश करता है, क्योंकि उन इलाकों में लोग अपना तटीय इलाका खो रहे हैं। समुद्र के बढ़ते जलस्तर का असर सिर्फ तटीय इलाकों तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने कहा, 'कृपया समुद्र के बढ़ते जलस्तर को एक बड़ी व्यवस्थागत समस्या के तौर पर देखें, क्योंकि इसका असर सेहत, खाद्य सुरक्षा, मानवाधिकारों और संस्कृति पर पड़ेगा। आप अपनी पुश्तैनी जमीन और अपनी पहचान खो देंगे। इसलिए सरकारों को इस मुद्दे को अपनी योजना बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाने के लिए बहुत व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। '

पिछले सप्ताह नेपाल-तिब्बत सीमा पर हिमालय से ग्लेशियर के टूटने और नीचे गिरने से पानी और कीचड़ का सुनामी जैसा सैलाब आया, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई और कई इलाके बर्बाद हो गए। दक्षिण एशिया पर ग्लेशियरों के पिघलने या नीचे गिरने के असर के बारे में पूछे जाने पर हनीफ ने कहा कि हिमालय के ग्लेशियरों को 'तीसरा ध्रुव' माना जाता है।

उन्होंने कहा, 'हमारे पास उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हैं और दक्षिण एशिया में दुनिया के ग्लेशियरों का बड़ा जमावड़ा होने के कारण इसे 'तीसरा ध्रुव' माना जाता है। अगले 15 से 20 सालों में दक्षिण एशिया के लिए ग्लेशियरों के पिघलने से बाढ़ का खतरा है। उन्होंने कहा कि इसके बाद सूखा पड़ सकता है, जिससे फसलें और खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो सकती है और बड़े जोखिम पैदा हो सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में लगभग 77 करोड़ लोग, यानी धरती पर हर दस में से लगभग एक व्यक्ति खतरे में हैं, क्योंकि वे ऐसे तटीय इलाकों में रहते हैं, जो हाई-टाइड लाइन (ज्वार-भाटा के दौरान पानी के अधिकतम स्तर की रेखा) से पांच मीटर से भी कम ऊंचे हैं और पहले से ही बड़े खतरों का सामना कर रहे हैं। अनुमान है कि दुनिया भर में समुद्र का जलस्तर बढ़ने से जुड़े खतरों के कारण कम से कम 1.8 ट्रिलियन डॉलर की कीमत वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को खतरा है।

रिपोर्ट में कहा गया है, 'समुद्र का जलस्तर बढ़ने से पहले ही शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, जल प्रणालियों, परिवहन, ऊर्जा ग्रिड, इमारतों और भूजल संसाधनों को नुकसान पहुंच रहा है। इसके दूरगामी परिणाम हो रहे हैं, जो लंबे समय में मानवाधिकारों के प्रभावी उपभोग के लिए खतरा पैदा करते हैं। '

रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि समुद्र का जलस्तर बढ़ने का खतरा सबसे अधिक द्वीपीय देशों को महसूस होगा, लेकिन यह खतरा भौगोलिक सीमाओं को नहीं मानता। रिपोर्ट में कहा गया है, 'उदाहरण के लिए, अमेरिका में मियामी और न्यूयॉर्क और चीन में ग्वांगझू जैसे अधिक आय वाले शहरों में मुख्य असर तटीय इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ने वाला भारी वित्तीय जोखिम है, जिसमें खतरे में पड़ी संपत्तियों का अनुमानित मूल्य 2 ट्रिलियन डॉलर से 3.5 ट्रिलियन डॉलर के बीच है।

साठगांठ: चुनाव अभियान के तहत हजारों डॉलर देकर बनवाए जा रहे वीडियो

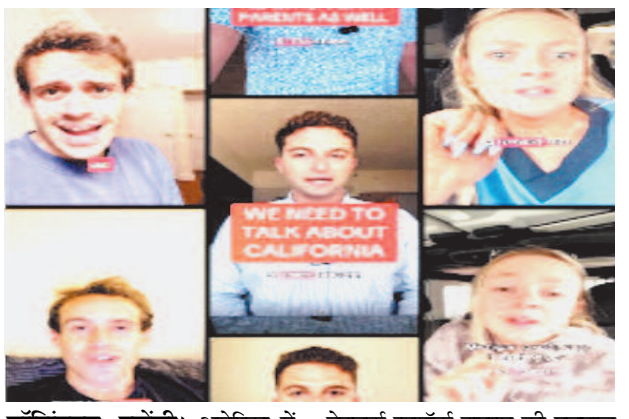

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में चुनाव प्रचार का मैदान तेजी से सोशल मीडिया की ओर खिसक रहा है। उम्मीदवार और उनके अभियान अब टीवी विज्ञापनों और रैलियों के साथ लोकप्रिय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी अपने संदेश का माध्यम बना रहे हैं। लाखों फॉलोअर्स वाले इन क्रिएटर्स की सामान्य वीडियो सामग्री दर्शकों को पारंपरिक राजनीतिक विज्ञापन की तुलना में ज्यादा सहज और विश्वसनीय लगती है। चिंता की बात यह है कि कई मामलों में इन्फ्लुएंसर्स को हजारों डॉलर देकर उम्मीदवारों या राजनीतिक मुद्दों के समर्थन में वीडियो बनवाए गए, लेकिन दर्शकों को स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया कि इन पोस्ट के लिए भुगतान किया गया है। इससे किसी इन्फ्लुएंसर की निजी राय और पैसे लेकर तैयार किए गए राजनीतिक संदेश के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है। पेड प्रचार का यह नेटवर्क न्यूयॉर्क टाइम्स की पड़ताल में सामने आया है। पड़ताल के दौरान पाया गया कि कैलिफोर्निया के गवर्नर पद के लिए उम्मीदवार टॉम स्टेयर के अभियान ने फरवरी से अगस्त के बीच कम से कम 17 इन्फ्लुएंसर्स को 5,000 डॉलर या उससे अधिक का भुगतान किया। इनमें टिकटॉक पर 14 लाख से अधिक फॉलोअर्स वाले कार्लोस एडुआर्डो एस्पिना भी शामिल थे। पूर्व प्रतिनिधि कैटी पोर्टर के अभियान ने 12 इन्फ्लुएंसर्स को कुल 1,39,500 डॉलर दिए। लाइफस्टाइल क्रिएटर एवरी साइरस को एक पोस्ट के लिए 25,000 डॉलर मिले। असल मुद्दा यह नहीं कि इंफ्लूएंसर्स प्रचार का हिस्सा बन रहे, बल्कि सवाल यह है कि लोगों के सामने जाहिर की जा रही उनकी राय कितनी स्वतंत्र है। कैलिफोर्निया में राजनीतिक पेड पोस्ट के लिए भुगतान की जानकारी देने के नियम हैं, लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा।

व्हाइट हाउस में 40 करोड़ डॉलर के बॉलरूम निर्माण को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने 'व्हाइट हाउस' (अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास एवं कार्यालय) में प्रस्तावित 40 करोड़ डॉलर के भव्य बॉलरूम के निर्माण को फिलहाल जारी रखने की सोमवार को अनुमति दे दी। अदालत के इस फैसले को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, जो अभूतपूर्व कार्यकारी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राजधानी की तस्वीर और स्वरूप को अपनी प्राथमिकताओं के अनुरूप बदलने का काम कर रहे हैं। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स के उस अस्थायी आदेश की जगह लेगा, जो उन्होंने अधीनस्थ अदालत के निर्माण कार्य रोकने के फैसले के प्रभावी होने से कुछ घंटे पहले जारी किया था।

हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने सोमवार के ताजा आदेश से सार्वजनिक रूप से असहमति जताई और उन्होंने अदालत के तीन उदारवादी न्यायाधीशों का साथ दिया जिन्होंने निर्माण परियोजना को 'संभावित रूप से गैरकानूनी' करार दिया। बहुमत में न्यायाधीशों ने परियोजना की वैधता पर कोई अंतिम फैसला नहीं दिया। उनका कहना है कि निर्माण को चुनौती देने वाले संरक्षण समूह के पास संभवतः ऐसा करने का कानूनी अधिकार नहीं है।

मामले पर सुनवाई अब अधीनस्थ अदालतों में होगी। हालांकि, अदालती दस्तावेजों के अनुसार परियोजना के अहम हिस्से अगले कुछ महीनों में ही पूरे हो सकते हैं। इस मामले में अधीनस्थ संघीय अदालतों ने परियोजना पर रोक लगाते हुए कहा था कि इसके लिए कांग्रेस (संसद) की मंजूरी जरूरी है जिसके बाद ट्रंप प्रशासन ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया। 'नेशनल ट्रस्ट फॉर हिस्टोरिक प्रिजर्वेशन' ने मुकदमा दायर कर कहा है कि ट्रंप को एकतरफा तरीके से यह काम शुरू करने का अधिकार नहीं है। परियोजना के तहत 'व्हाइट हाउस' के ईस्ट विंग को गिराया जा चुका है। संगठन के वकीलों का आरोप है कि 'व्हाइट हाउस' निर्माण कार्य में तेजी लाकर 'अदालतों की सुनवाई से पहले ही काम पूरा करने' की कोशिश कर रहा है।

'उन पर कड़ा प्रहार करेंगे', जॉर्डन में मिसाइल अटैक के बाद ट्रंप ने ईरान को दी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी

वॉशिंगटन, एजेंसी। ईरान की कार्रवाई के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। सोमवार (स्थानीय समयानुसार) ट्रंप ने कहा कि ईरान ने रात के दौरान जॉर्डन में तैनात अमेरिकी बलों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। अमेरिका इसका जवाब देगा। फॉक्स न्यूज को दिए एक फोन इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, 'हम उन पर कड़ा प्रहार करेंगे। इसका जवाब दिया जाएगा।' राष्ट्रपति ने बताया कि रात में दागी गई ईरानी मिसाइलों में से एक को अमेरिकी वायु रक्षा प्रणाली ने जानबूझकर नहीं रोका, क्योंकि आकलन में पाया गया था कि वह किसी लक्ष्य को नहीं लगेगी। वहीं, बाकी आने वाली मिसाइलों को बीच रास्ते में ही रोक दिया गया। हालांकि, ट्रंप ने कहा कि बातचीत की संभावना अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा, 'वे बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि उनके साथ किसी समझौते पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं।' ट्रंप ने कहा कि 'प्रतिबंधों का असर अब बहुत मजबूती से दिखाई दे रहा है। फॉक्स न्यूज ने एक अमेरिकी सूत्र के हवाले से बताया कि ईरान ने रविवार को जॉर्डन में अमेरिकी बलों पर कम से कम आठ बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। यह हमला अमेरिका की ओर से लारक द्वीप पर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के मिसाइल लॉन्चरों पर किए गए हवाई हमले के बाद हुआ। रिपोर्ट के अनुसार, इस हमले से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। दूसरी ओर, ईरान की फर्स न्यूज एजेंसी ने आईआरजीसी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि ईरानी सेना ने जॉर्डन में स्थित किंग हुसैन और अल-अजराक अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मौजूद 'तकनीकी और रखरखाव ढांचे' तथा उन क्षेत्रों को निशाना बनाया जहां 'दुश्मन के लड़ाकू विमान' तैनात थे। ईरान का दावा है कि इस हमले से भारी नुकसान हुआ। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने लारक द्वीप पर किए गए हमले को 'सीमित और सटीक कार्रवाई' बताया। उसका कहना है कि यह कार्रवाई ईरान की उन माइन बिछाने वाली सैन्य क्षमताओं के खिलाफ की गई थी, जो होर्मुज स?ट्रेट से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों और वैश्विक व्यापार के लिए तत्काल खतरा पैदा कर रही थीं। हमले के बाद आईआरजीसी ने एक बयान में कहा कि इस कार्रवाई में कई सैन्यकर्मी और आम नागरिक मारे गए या घायल हुए हैं। संगठन ने कहा कि इस हमले का जवाब 'आक्रमणकारी को सजा देकर' दिया जाएगा। ईरान की अर्ध-सरकारी तस्नीम समाचार एजेंसी ने अनौपचारिक रिपोर्टों के आधार पर कहा कि लारक द्वीप पर हुए अमेरिकी 'ड्रोन हमले' में कम से कम दो लोगों की मौत हुई और दो अन्य घायल हुए हैं।

उत्तरी साइप्रस के तट पर फेरी डूबने से आठ यात्रियों की मौत, 18 लोग लापता

निकोसिया, एजेंसी। तुर्की साइप्रस अधिकारियों ने बताया कि उत्तरी साइप्रस तट के पास एक तुर्की फेरी के डूबने के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है, जबकि 18 लोग अब भी लापता हैं। डबल-हल वाली इस फेरी में 259 यात्री और 8 चालक दल के सदस्य सवार थे। रविवार दोपहर कायरिनिया बंदरगाह से रवाना होने के कुछ ही समय बाद फेरी में पानी भरना शुरू हो गया और वह पलट गई। अधिकारियों के अनुसार, सोमवार तक 241 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया था। स?ेन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार, पलटने बाद में फेरी समुद्र में 500 मीटर से अधिक गहराई में डूब गई। यह अभी साफ नहीं है कि कोई व्यक्ति जहाज के अंदर फंसा था या नहीं। हालांकि सोशल मीडिया पर सामने आए कुछ वीडियो से संकेत मिला कि फेरी के डूबने के समय उसके एक हिस्से में अभी भी कुछ लोग मौजूद थे। तुर्की ने बताया कि वह खोज अभियान में मदद के लिए एक गहरे समुद्र में काम करने वाला रिमोट संचालित वाहन (आरओवी) भेज रहा है। यह उपकरण मंगलवार तक दुर्घटनास्थल पर पहुंचने की उम्मीद है। तुर्की साइप्रस अधिकारियों ने फेरी के कप्तान और चालक दल के सात अन्य सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। स्थानीय मीडिया के अनुसार, इस फेरी में पहले भी पानी रिसने की समस्या रही थी और उसकी मरम्मत कराई गई थी। कुछ बचे हुए यात्रियों ने दावा किया कि कप्तान और चालक दल के सदस्य सबसे पहले नाव से बाहर निकल गए और यात्रियों को सुरक्षित निकलने के लिए कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए। शनिवार को साइप्रस में तेज तूफान आया था और रविवार को भी समुद्र की स्थिति काफी खराब बनी हुई थी। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि उस समय मौसम को देखते हुए फेरी का कायरिनिया से लगभग 120 किलोमीटर उत्तर में स्थित तुर्की के तासुकु बंदरगाह के लिए रवाना होना सुरक्षित माना गया था। अधिकारियों ने कहा कि फेरी के पलटने की असली वजह की जांच अभी जारी है। इस साल की शुरुआत में सूडान में भी इसी तरह की एक घटना हुई थी। उत्तरी सूडान के नील राज्य में एक यात्री फेरी नदी में डूब गई थी, जिसमें कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी। सूडान की सिविल डिफेंस अथॉरिटी के एक अधिकारी के अनुसार, ऊंची लहरों के कारण नाव पलट गई थी। बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर 15 से अधिक शव बरामद किए थे। इस हादसे में 8 लोग बच गए थे, जबकि लगभग 4 लोग लापता बताए गए थे। फिलहाल साइप्रस में डूबी फेरी के लापता यात्रियों की तलाश जारी है और बचाव दल उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बाकी लोगों का पता लगाया जा सके।

राहुल पर एफआईआर को लेकर भड़के सैम पित्रोदा

न्यूयॉर्क , एजेंसी। भारतीय ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने अमेरिका में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत के हालिया कार्यक्रम और उनके 'मानवता की एकता' वाले बयान पर सवाल उठाए हैं। पित्रोदा ने कहा कि केवल बयान देने से बात नहीं बनती, बल्कि किसी विचार की असली परीक्षा उसके अमल में होती है।

भागवत के बयान पर पित्रोदा ने क्या कहा : मोहन भागवत ने न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में आयोजित 'वन वर्ल्ड वन ह्यूमैनिटी' कार्यक्रम में कहा था कि अलग-अलग धर्म भले ही अलग रास्तों पर चलते हों, लेकिन मानवता और सत्य एक हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हर इंसान की गरिमा समान है। भागवत के इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पित्रोदा ने कहा कि भारत में मुस्लिम, ईसाई, यहूदी और बौद्ध समुदाय के लोगों से पूछा जाना चाहिए कि वे मौजूदा हालात को किस तरह देखते हैं। पित्रोदा ने कहा कि एक तरफ सभी का सम्मान करने की बात कही जाती है और दूसरी तरफ किसी के साथ मारपीट की घटनाएं होती हैं। उनके मुताबिक, 'बातों से ज्यादा काम मायने रखता है।

अमेरिका में भागवत के कार्यक्रम को लेकर क्यों हुआ विवाद : आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अपने संगठन के शताब्दी वर्ष के वैश्विक संपर्क अभियान के तहत अमेरिका पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भारतीय प्रवासियों, भारतीय-अमेरिकी कारोबारियों और विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। न्यूयॉर्क में उनके कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक विरोध भी देखने को मिला। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने भागवत की यात्रा का विरोध किया था। कुछ नगर परिषद सदस्यों ने भी कार्यक्रम स्थल पर आयोजन रद्द करने की मांग की थी। हल्द्वानी में शुद्धिकरण विवाद को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर भी पित्रोदा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कांग्रेस नेता की तारीफ करते हुए राहुल गांधी को मजबूत और दृढ़ नेता बताया। पित्रोदा ने दावा किया कि देश की संस्थाओं में सत्ता के अत्यधिक केंद्रीकरण का असर पड़ा है। उन्होंने न्यायपालिका, चुनाव आयोग, प्रवर्तन निदेशालय और स्थानीय पुलिस समेत कई संस्थाओं की स्वतंत्र भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए। पित्रोदा ने हाल में संपन्न संसद के मानसून सत्र को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि संसद में बहस के दौरान कई बार एक-दूसरे पर चिल्लाने की स्थिति दिखाई देती है। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के प्रदर्शन की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार कई मुद्दों पर दबाव में नजर आई। भारत की वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8 फीसदी वास्तविक जीडीपी वृद्धि के आंकड़ों पर भी सैम पित्रोदा ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास का आकलन केवल आंकड़ों से नहीं, बल्कि इस आधार पर भी होना चाहिए कि उसका फायदा आम लोगों तक कितना पहुंचा। पित्रोदा ने पूछा कि क्या यह वृद्धि देश के लोगों के लिए है।

नेपाल बाढ़ : त्रासदी में अब तक 939 लोगों ने गंवाई जान, करीब 4000 लापता; राहत एवं बचाव अभियान जारी

काठमांडो , एजेंसी। नेपाल-तिब्बत सीमा के पास भोटेकोशी नदी में 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ ने दोनों ही देशों के इलाकों में भीषण तबाही मचाई है। इस बाढ़ में अब तक 939 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 4000 लोग अब भी लापता हैं। नेपाल-तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। वहीं, नेपाल के नुवाकोट के बिदुर में सेना की ओर से बचाव अभियान जारी है। बाढ़ से भोटेकोशी और त्रिशूली नदी प्रणालियों के प्रभावित होने के कारण त्रिशूली क्षेत्र के एक बाजार में कई दुकानें नष्ट हो गईं। बताया जा रहा है कि नुवाकोट में संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है।

भारतीय टनल टीम ने संभाला मोर्चा, 158 भारतीयों का रेस्क्यू : काठमांडू। नेपाल और तिब्बत सीमा पर 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन के बाद स्थिति भयावह बनी हुई है। सोमवार को नेपाल के नुवाकोट स्थित बिदुर इलाके में मलबे में तब्दील हो चुके एक ही घर से बच्चे समेत 24 शव बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार मलबे में अभी और शव दबे होने की आशंका है। आपदा में अब तक कुल 955 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है (नेपाल में 939 और तिब्बत में 16), जबकि 4,471 लोग अब भी लापता हैं। करीब 65 हजार प्रभावितों तक तात्कालिक राहत सामग्री पहुंचाई गई है। विदेश मंत्रालय के अनुसार पिछले सप्ताह आई बाढ़ के बाद से अब तक 158 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।

हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स में टनल रेस्क्यू: नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव के अनुसार, भारतीय टनल रेस्क्यू टीम ने नेपाली सेना के साथ मिलकर चिलिमे और लांगटांग जलविद्युत परियोजनाओं में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। चिलिमे में टीम दुर्गम रास्तों को पार कर सुरंग तक पहुंच गई है, जबकि लांगटांग में सुरंग के 185 मीटर भीतर तक सघन तलाशी ली गई है। फॉरेंसिक सहायताः भारतीय फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम काठमांडू स्थित नेपाल पुलिस की सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब के साथ मिलकर मृतकों की पहचान और दस्तावेजीकरण में सहयोग कर रही है।

उत्तर प्रदेश में गंडक नदी से मिले 17 शव : कुशीनगर व महराजगंज में रिकवरीः नेपाल में आई बाढ़ के तेज बहाव में बहकर उत्तर प्रदेश की गंडक नदी में पहुंचे 17 शव बरामद किए गए हैं। इनमें 13 शव कुशीनगर (खड्डा और तमकुही राज तहसील) से मिले हैं, जबकि महराजगंज से मिले 4 शवों (3 महिलाएं शामिल) को पोस्टमार्टम और डीएनए सैंपलिंग के बाद नेपाल प्रशासन को सौंप दिया गया है। नेपाल सरकार ने बनाया 21-दिवसीय टास्क फोर्स, चीन का दावा

21 दिन का एक्शन प्लान: नेपाल सरकार ने रसुवा के भोटेकोशी नदी से प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा बहाल करने के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है। यह टीम सड़क, झूला पुल, पेयजल, संचार और स्वास्थ्य सेवाओं को 21 दिनों के भीतर युद्धस्तर पर बहाल करेगी।

डेटा साझा करने पर चीन की सफाई: पूर्व चेतावनी न देने के आरोपों पर चीन ने स्पष्ट किया कि उसके वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर ने घटना से 12 दिन पूर्व ही नेपाल को भारी बारिश, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड को लेकर ईमेल के जरिए अलर्ट भेज दिया था।

स्वामी,मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

अन्ना की तबीयत में सुधार, महाराष्ट्र के सीएम ने अस्पताल पहुंचकर जाना हाल

मुंबई (एजेंसी)। मुंबई में भर्ती अन्ना हजारे की तबीयत में सुधार हो रहा है। अब डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक वे खाना खा रहे हैं। उनके करीबी सहयोगी ने बुधवार को यह जानकारी दी। डॉक्टरों के मुताबिक अन्ना हजारे को अभी दो दिन और अस्पताल में निगरानी में रखा जाएगा। उनके सहयोगी ने बताया कि डॉक्टरों ने उनकी जांच की है और उनकी हालत में सुधार हुआ है। पूरी तरह ठीक होने के बाद वह अपने गांव जा सकेंगे। बता दें अन्ना हजारे को सोमवार रात मुंबई के बॉम्बे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इससे पहले उनके ब्लड टेस्ट में किडनी में संक्रमण के संकेत मिले थे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार शाम अस्पताल पहुंचकर अन्ना हजारे से मुलाकात की और उनकी तबीयत के बारे में जानकारी ली।

सिकंदराबाद छावनी से बड़े पैमाने पर हथियार चोरी, हाई अलर्ट जारी

सिकंदराबाद (एजेंसी)। तेलंगाना के सिकंदराबाद कैंटोनमेंट स्थित सेना की मद्रास रेजिमेंट परिसर से 5 असॉल्ट राइफलें (जिसमें 4 एके-सीरीज की), 7 पिस्तौल, 21 मैगजीन और लगभग 19,000 राउंड गोला-बारूद चोरी हो गए हैं। बदमाशों ने हथियार रखने वाली बैरक का दरवाजा तोड़कर बड़ी वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद सेना ने पूरे सिकंदराबाद छावनी को हाई अलर्ट पर रखा है, जिसमें अधिकारियों के आवागमन की कड़ी जांच और सुरक्षा एस्कॉर्ट में वृद्धि शामिल है। पुलिस ने भारतीय सेना की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर संदिग्धों की तलाश तेज की है। पुलिस सूत्रों का मानना है कि चोरी के पीछे दो से ज्यादा लोग हैं और उन्हें परिसर के बारे में अच्छी जानकारी थी। मामले की जांच के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो दोषियों को पकड़ने के प्रयास में लगी हैं। इस घटना ने हथियार रखने की जगह के आसपास उचित सुरक्षा न होने पर भी चिंताएँ बढ़ा दी हैं।

सिब्बल का आरोप : मतदाता सूची में हेरफेर के लिए बना एसआईआर

-सुप्रीम कोर्ट से लगाई रोक की गुहार

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग द्वारा हो रही एसआईआर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस प्रक्रिया को मतदाता सूची में हेरफेर की एक सोची-समझी कवायद बताया है, जिसका उद्देश्य भाजपा को आगामी चुनावों में फायदा पहुंचाना है। वरिष्ठ वकील सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से इस पूरी प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री की यह टिप्पणी मीडिया रिपोर्ट के बाद आई है, जिसमें दावा किया गया था कि झारखंड के गोड्डा जिले में भाजपा के एजेंट अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि स्थानीय बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) इसका विरोध कर रहे हैं। वरिष्ठ वकील सिब्बल ने घटनाक्रम को बहिष्कार की राजनीति करार दिया, जिसमें बड़े पैमाने पर मुसलमानों को निशाना बनाकर उनके नाम सूची से हटवाए जा रहे हैं। सिब्बल ने कहा कि एसआईआर सिर्फ बहाना है, जिसके जरिए मतदाता सूची में छेड़छाड़ कर भाजपा को चुनाव जीतने में मदद की जा रही है। उन्होंने चुनाव आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार पर भी आरोप लगाए। सिब्बल ने कहा कि झारखंड और दिल्ली में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के पीछे ज्ञानेश कुमार का मकसद है, ताकि भाजपा के लोगों को उन मतदाताओं के नाम काटने का मौका मिल सके जो उन्हें वोट नहीं देते हैं, चाहे वे मुस्लिम हों या कांग्रेसी। वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस पर दुख व्यक्त किया कि अदालतें इसतरह के गंभीर मुद्दों का संज्ञान नहीं ले रही हैं। उन्होंने जोर दिया कि यदि किसी गरीब व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से कट जाता है, तब उस गरीब इंसान को भारी नुकसान होता है, क्योंकि उसके पास अपना नाम दोबारा जुड़वाने के लिए पर्याप्त साधन नहीं होते। इसलिए, सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से इस हेरफेर को रोकने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने का आग्रह किया है।

फरीदाबाद छात्रा आत्महत्या : स्कूल में बर्बर सजा और अपमान के आरोप

फरीदाबाद (एजेंसी)। हरियाणा के फरीदाबाद में 11वीं कक्षा की छात्रा द्वारा स्कूल की तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या करने के मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। छात्रा के पिता ने आरोप लगाया था कि एक शिक्षक की सजा के बाद उनकी बेटी ने कदम उठाया। अब, अन्य अभिभावक भी सामने आए हैं, जिन्होंने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अभिभावकों का कहना है कि नवोदय विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कठोर दंड आम बात थी। आरोप है कि छात्रों को घंटों तक धूप में खड़ा रखा जाता था, उनकी पिटाई की जाती थी और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता था।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीजेपी ने वापस लिया आंदोलन, नड्डा ने किया स्वागत

नई दिल्ली, एजेंसी।
नीट परीक्षा से जुड़े मामलों को लेकर बीते महीने से आंदोलन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने आगामी 5 सितंबर को प्रस्तावित अपना राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन रद्द करने का ऐलान किया है। सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को आंदोलन की बड़ी सफलता बताया। उन्होंने कहा कि उनकी प्रमुख मांगें, जिसमें छात्रों पर दर्ज मामले वापस लेना और नीट से जुड़े आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को आर्थिक सहायता देना शामिल था, पर अब फैसला आ गया है। इस घोषणा के साथ ही दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने आंदोलन वापसी के फैसले का स्वागत किया है।

केंद्रीय मंत्री नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले ही छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखकर प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने और भविष्य में उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न करने का भरोसा दिया था। उन्होंने बताया कि इस बारे में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की सरकारों से भी बातचीत की गई है और अब सरकार अपने उस आश्वासन को पूरा कर रही है। केंद्रीय मंत्री नड्डा ने जोर दिया कि युवाओं की प्रगति और विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है।

दूसरी ओर, छत्रपति संभाजीनगर से सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को न्याय की बड़ी जीत बताया। उन्होंने दावा किया कि छात्र आंदोलन के दबाव के कारण ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था। दीपके ने कहा कि सरकार पहले उनकी मांगों को स्वीकार नहीं कर रही थी, लेकिन अब कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित परिवारों और छात्रों को न्याय मिला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दीपके ने नीट मामले से जुड़े आत्महत्या पीड़ित छात्रों के परिवारों से भी बातचीत की और उन्हें हर संभव सहारा देने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि दिल्ली में आंदोलन से जुड़े साथियों के साथ कई दौर की बैठकों के बाद सर्वसम्मति से 5 सितंबर के आंदोलन को रद्द करने का निर्णय लिया गया।

भारत ने पांचवां विमान राहत सामग्री और विशेष रेस्क्यू टीम के साथ नेपाल भेजा

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत ने नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ और आपदा से राहत के लिए अपना पांचवां विमान भी राहत सामग्री और विशेष रेस्क्यू टीम के साथ रवाना कर दिया है। इस मदद को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत की ओर से 5.5 टन जरूरी दवाइयां, विशेष बचाव उपकरण और 11 सदस्यों की एक विशेष रेस्क्यू टीम लेकर पांचवां विमान नेपाल के लिए रवाना हो गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले भारत मानवीय सहायता और आपदा राहत के तहत नेपाल को कुल चार खेप भेज चुका है, जिसमें करीब 57.5 टन से ज्यादा राहत सामग्री, जनरेटर, मेडिकल टीमें, और खोज-बचाव दल शामिल हैं। भारत सरकार एनडीआरएफ के विशेषज्ञों और जरूरी उपकरणों के साथ नेपाल में फंसे लोगों को निकालने और बुनियादी संपर्क बहाल करने में लगातार मदद कर रहा है। भारत ने 19 सदस्यों वाली 6 फोरेंसिक टीमों को काठमांडू भेजा है। ये टीमें शवों के डीएनए सैंपलिंग और उनकी पहचान करने में नेपाल के प्रशासन की मदद कर रही हैं। भारत ने 230 फीट लंबा सिंगल-लेन मॉड्यूलर स्टील ब्रिज बनाने के लिए 16 ट्रक उपकरण नेपाल पहुंचाए हैं। संपर्क मार्गों को तुरंत चालू करने के लिए 7 अतिरिक्त बेली ब्रिज और उन्हें जल्द इंस्टॉल करने के लिए तकनीकी दल भी भेजे जा रहे हैं। भारत ने विशिष्ट उपकरणों से लैस 13 सदस्यीय विशेषज्ञ सेना टीम को टनल ऑपरेशन्स के लिए भेजा।

सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार: 70,500 से अधिक शिकायतें, बैंक और रेलवे शीर्ष पर

-केंद्रीय सतर्कता आयोग की हालिया रिपोर्ट में खुलासा

नई दिल्ली, एजेंसी।
केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की हालिया रिपोर्ट ने बीते साल सरकारी संस्थानों के खिलाफ भ्रष्टाचार की भयावह तस्वीर पेश की है, जिसमें 70,500 से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें सबसे अधिक शिकायतें बैंकिंग और रेलवे जैसे प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित थीं, जो इन विभागों में व्याप्त अनियमितताओं को दिखाती हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, आयोग के मुख्य सतर्कता अधिकारियों (सीवीओ) को कुल 70,584 शिकायतें मिली थीं। इसमें से बीते साल 31 दिसंबर तक 64,905 शिकायतों का निपटारा किया गया। हालांकि, 5,679 शिकायतें अभी भी लंबित थीं, जिसमें से 2,002 शिकायतें तीन महीने से अधिक समय से फंसी हुई हैं। सीवीओ से आमतौर पर 3 महीने के भीतर शिकायतों का निपटारा करने की अपेक्षा की जाती है, और आयोग लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करता है।
आंकड़ों के मुताबिक, बैंकों के सीवीओ को सर्वाधिक 9,933 शिकायतें मिलीं। इसमें से 9,520 का निपटारा हो गया, लेकिन 413 शिकायतें लंबित रहीं, जिसमें 52 शिकायतें 3 महीने से अधिक समय से लंबित थीं। रेलवे भी इस सूची में पीछे नहीं रहा, जहां 9,381 शिकायतें दर्ज की गईं। इसमें से 8,754 का निपटारा किया गया, जबकि 627 शिकायतें लंबित थीं, जिसमें से 10 शिकायतें तीन महीने से अधिक पुरानी थीं।
अन्य प्रमुख क्षेत्रों में आवास और शहरी मामलों से जुड़ी 6,531 शिकायतें, दिल्ली सरकार को छोड़कर स्थानीय निकायों से 4,834, कोयला क्षेत्र से 4,118, वित्त क्षेत्र से 3,107 और दिल्ली सरकार से 2,804 शिकायतें शामिल थीं। पेट्रोलियम मंत्रालय के खिलाफ 2,722, दिल्ली पुलिस के खिलाफ 2,633 और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग क्षेत्र से संबंधित 2,139 शिकायतें भी प्राप्त हुईं। रिपोर्ट में सीवीसी द्वारा आवश्यक कार्रवाई के लिए सीवीओ को भेजी गई 18,651 शिकायतों का भी उल्लेख है, जिसमें स्थानीय निकायों (4,110), बैंकों (1,749) और रेलवे (1,428) से संबंधित शिकायतें शीर्ष पर थीं। यह रिपोर्ट सरकारी विभागों में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी पर गंभीर सवाल उठाती है।

बीजेपी नेता रील्स बनाने, फॉलोअर्स बढ़ाने और अपने फैन क्लब बनाने में व्यस्त

पश्चिम बंगाल विधायक अमरनाथ ने अपनी ही पार्टी नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप

कोलकाता, एजेंसी।
पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले की ओंडा विधानसभा से बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अमरनाथ शाखा ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने फेसबुक पर की गई अपनी एक तीखी पोस्ट में आरोप लगाया कि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी जमीनी मुद्दों पर माकपा (सीपीआई-एम) और लेफ्ट फ्रंट का मुकाबला करने के बजाय केवल रील्स बनाने, फॉलोअर्स बढ़ाने और अपने फैन क्लब बनाने में व्यस्त हैं।

उन्होंने कहा कि इतने लंबे समय से इस पार्टी में सक्रिय रहने के कारण कुछ चीजें देखकर मैं चुप नहीं रह सकता। मैं दूसरों को खुश करने में विश्वास नहीं रखता, जो मुझे गलत लगता है, उसके खिलाफ आवाज उठाता हूं और इसी वजह से मेरे कई दुश्मन बन गए हैं। हालांकि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी पूरी जिंदगी संघर्षों से भरी है। उन्होंने कहा कि मैं कभी ऐसा इंसान नहीं रहा और न ही बनना चाहता हूं, जो सामने वाले व्यक्ति के हिसाब से अपना स्वभाव बदल ले।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरनाथ ने फेसबुक पोस्ट में कहा कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है, लेफ्ट फ्रंट उकसावे और गलत जानकारी फैलाकर जनता की नजर में सरकार की छवि खराब करने में लगा है फिर भी हमारे वरिष्ठ नेता कोई विरोध नहीं करते। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक वे बस अपना प्रचार करने में ही लगे रहते हैं। उन्हें लगता है कि पार्टी भाड़ में जाए, बस हमारा पेट भरा रहना चाहिए, यही मायने रखता है।
उन्होंने आरोप लगाया कि हर कोई रील्स बनाने, फॉलोअर्स बढ़ाने और अपने फैन क्लब को बड़ा करने में व्यस्त है। सरकार के सत्ता में आने के बाद से उनकी शान-ओ-शौकत बहुत बढ़ गई है देखिए वे कहां से शुरू हुए थे और अब कहां पहुंच गए हैं। उन्हें पार्टी के प्रति कोई जवाबदेही महसूस नहीं होती। उन्होंने कहा कि किसी खास नेता का फॉलोअर बनने के बजाय, पहले पार्टी के प्रति वफादार बनिए। नेता तो आते-जाते रहेंगे, लेकिन पार्टी बनी रहेगी। मैंने अपनी जवानी, परिवार और बाकी सब कुछ छोड़कर अपना पूरा जीवन इस पार्टी को समर्पित किया है। 34 सालों तक मैंने सीपीएम की धमकियों और आतंक के साथ-साथ तृणमूल के अत्याचारों का भी सामना किया है। इन सबके बावजूद लोगों ने हम पर भरोसा बनाए रखा। फिर भी कुछ लोगों की वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है और उन लोगों का ध्यान सिर्फ पैसा कमाने पर है।

महुआ मोइत्रा की सुरक्षा बढ़ी : कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्देश

कोलकाता (एजेंसी)। ,(ईएमएस)। तृणमूल कांग्रेस की नेता और कृष्णानगर से सांसद महुआ मोइत्रा की सुरक्षा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोलकता की अदालत ने निर्देश दिया कि मोइत्रा को उनकी मौजूदा निजी सुरक्षा के अलावा दो और पुलिस सुरक्षाकर्मी मुहैया कराए। सांसद महुआ ने अपने संसदीय क्षेत्र में काम करने के दौरान आ रही दिक्कतों और सुरक्षा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनका आरोप था कि कृष्णानगर लोकसभा क्षेत्र में उन्हें बार-बार बीजेपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के विरोध और हमलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें अपने काम में दिक्कतें आ रही हैं। मामले पर सुनवाई कर जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की सिंगल बेंच ने कृष्णानगर जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को सांसद की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, महुआ को अगले 30 दिनों के दौरान अपने लोकसभा क्षेत्र के दौरों के समय दो अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी। हालांकि, अदालत ने शर्त भी तय की है कि अपने संसदीय क्षेत्र में किसी भी दौरे पर जाने से करीब 48 घंटे पहले महुआ मोइत्रा को ईमेल के जरिए जिले के एसपी को लिखित सूचना देनी होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से जारी किया गया यह अंतरिम आदेश 1 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 अक्टूबर की तारीख तय की है, जिस दौरान पुलिस प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था और उठाए गए कदमों को लेकर कोर्ट में रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया गया है।

चिन्नागवुर में बुजुर्ग महिला को सीएम विजय ने पहना दिया 40 हजार का सनग्लास

मेट्टूर डैम के गेट खुलवाकर पानी छोड़ा, किसानों को धोती-साड़ियां भी बांटी

चेन्नई, एजेंसी।
तमिलनाडु के सीएम विजय ने मेट्टूर में कावेरी डेल्टा जिलों में सिंचाई के लिए मेट्टूर डैम के गेट खुलवाए और पानी छोड़ा। सलेम जाते समय वे चिन्नागवुर में बुजुर्ग महिला चेल्लम के घर गए। विजय ने चेल्लम से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। इसी दौरान उन्होंने अपना डियोर का सनग्लास उतारकर चेल्लम को दे दिया। इसकी कीमत करीब 40 हजार रुपए बताई जा रही है। चेल्लम ने सनग्लास पहनकर अभिवादन किया और कहा कि विजय को अचानक सामने देखकर वह हैरान रह गईं। विजय उन्हें फिल्मी हीरो जैसे लगे। विजय ने उनसे पूछा कि उन्होंने खाना खाया या नहीं। चेल्लम ने बताया कि वह उनका इंतजार कर रही थीं। विजय ने उन्हें खाना खाने को कहा और बताया कि वह खुद खाना खा चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विजय का यह दौरा पहले से तय नहीं था। मेट्टूर से एयरपोर्ट जाते समय वे खेत के पास रुके और बुजुर्ग महिलाओं से मिले। विजय किसान पलानीसामी के पशु शेड में गए और लोगों से बातचीत की। उन्होंने चेल्लम को साड़ी और किसानों को सिल्क की धोती-साड़ियां बांटी। 15 मिनट के इस दौरे का वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उन्होंने कहा कि अगर कोई विजय को नुकसान पहुंचाएगा तो वह उनका बचाव करेंगी। चेल्लम ने अपनी निजी परेशानी नहीं बताई। रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें राशन कार्ड की समस्या है और उम्र के कारण वह काम नहीं कर पाती हैं।

ओवैसी की पार्टी को उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले झटका?

-राष्ट्रीय प्रवक्ता के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें

लखनऊ, एजेंसी।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली पार्टी एआईएमआईएम को एक बड़ा झटका लग सकता है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद असीम वकार के कांग्रेस में शामिल होने की खबरें सामने आ रही हैं। सूत्रों के अनुसार, वकार गुरुवार तक दिल्ली में कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, हालांकि उन्होंने इन खबरों की न तो पुष्टि की है और न ही खंडन किया है। वकार पिछले लगभग एक दशक से ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से जुड़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में उनकी अच्छी पहचान है। ऐसे में, यदि वे पार्टी छोड़ते हैं, तो यह उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने और सीटें जीतने की एआईएमआईएम की कोशिशों के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है।
असीम वकार का एआईएमआईएम में महत्व काफी अधिक है, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख राज्य में जहाँ पार्टी अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। एक राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में, वे पार्टी के विचारों और रणनीतियों को जनता तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसी जानकारी मिली है कि वकार पिछले कुछ समय से पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई से जुड़े फैसलों को लेकर नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। एआईएमआईएम में शामिल होने से पहले, वे लगभग 20 साल तक समाजवादी पार्टी में भी रहे थे, जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी गहरी जड़ें स्पष्ट होती हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने वकार के कांग्रेस में जाने की योजना में अहम भूमिका निभाई है। असदुद्दीन ओवैसी ने अभी यह तय नहीं किया है कि एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि पार्टी विधानसभा चुनाव निश्चित रूप से लड़ेगी और सीटें जीतने की पूरी कोशिश करेगी। पिछले महीने, ओवैसी ने यह दावा किया था कि पार्टी का संगठन पहले की तुलना में काफी मजबूत हुआ है और जनता में एआईएमआईएम को एक विकल्प के तौर पर देखने की सोच भी प्रबल हुई है।

चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से ऊपर, 400 दुकानें और 20 होटल जलमग्न

उत्तराखंड में बारिश से जुड़े हादसों में 11 की मौत, बिहार के 14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी।
देश के कई राज्यों में मानसूनी बारिश का तांडव जारी है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। रामघाट क्षेत्र में करीब 400 दुकानें और 20-25 होटल जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन ने तटवर्ती 36 गांवों में हाई अलर्ट जारी किया है। वहीं एक नाविक के तेज बहाव में बहने की सूचना है, जिसकी तलाश जारी है। यूपी के सहारनपुर में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं, जिससे कई संपर्क मार्ग और पुल डूब गए हैं। वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर से रत्नेश्वर महादेव मंदिर का लगभग पानी में डूब गया है।
वहीं उत्तराखंड में बारिश से जुड़े हादसों में 11 लोगों की जान चली गई है। मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर नैनीताल, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिलों में सभी स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। हल्द्वानी में गौला नदी पूरे उफान पर है। पटना सहित कई इलाकों में तेज बारिश से जलभराव की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग ने पटना समेत राज्य के 14 जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रोहतास के मांझर कुंड झरने में फंसे दो युवकों को पानी घटने के बाद सुरक्षित निकाला गया।
झारखंड के पलामू में सोन नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। वहीं, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के सेमरिया गांव में बाढ़ के चलते ग्रामीणों को कमर तक पानी में चलकर अंतिम संस्कार के लिए जाना पड़ा। 3 सितंबर को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश का अनुमान है। 4 सितंबर को मध्य प्रदेश में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है।
उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से आम लोगों को जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। बीते कई दिनों से प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर हो रही बारिश के चलते तमाम नदियों को जलस्तर बढ़ गई हैं। गंगा-यमुना नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच गई हैं, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। यूपी में बीते 24 घंटों में पूर्वांचल के कई जिलों में मूसलाधार बारिश देखने को मिली है। पीलीभीत में शारदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। वहीं बनबसा बैराज से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की आशंका है। ऐसे में हालात और खराब हो सकते हैं।
वाराणसी में वरुणा नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह अब पानी तटवर्ती इलाकों में घुस गया है। तमाम घाट पानी में डूब गए हैं। कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। पानी बढ़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग ने आज भी बांदा, प्रयागराज, आगरा, मेरठ, झांसी, बरेली समेत 30 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी बारिश का दौर जारी रहेगा।